- 20th Year
- Issue: 101
- 10.08.2026 (MONDAY)
- ROURKELA
- R.N.I. No. ORIHIN/2006/18978
- (Pages-6)
- Price:2.00

दैनिक

कलिंग समाचार

The kalingasamachar

e-paper-www.thekalingasamachar.com

प्रकाशक एवं संपादक : प्रकाश कुमार धल

Published From ODISHA, JHARKHAND & CHHATTISHGARH

जेपीएससी-जेएसएससी विवाद पर छात्रों का अल्टीमेटम, मांगे नहीं मानी तो १० को करेंगे विधानसभा घेराव

रांची ०९/०८ (संवाददाता): झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और धांधली के आरोपों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन अब और तेज हो गया है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता रवींद्र पासवान ने राज्य सरकार पर छात्रों की एकता को तोड़ने और उन्हें भटकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने साफ अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो 10 अगस्त को पूरे राज्य के छात्र मिलकर विधानसभा का घेराव करेंगे। जेपीएससी-जेएसएससी सुधार मंच के नेता रवींद्र पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि छात्र पिछले 15 दिनों से लगातार धरने और भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं। शुक्रवार को सरकार के प्रतिनिधियों के साथ पहले दौर की बातचीत में छात्रों ने पूरे सबूतों और तर्कों के साथ अपनी बात रखी थी। सरकारी टीम ने भरोसा दिया था कि वे ये सारी बातें मुज़्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाएंगे। लेकिन पासवान का आरोप है कि सरकार दूसरे संगठनों से अलग-अलग बात करके इस आंदोलन को 2-3 हिस्सों में बांटने की कोशिश कर रही है। छात्र नेताओं ने झारखंड के सभी युवाओं से एकजुट रहने की अपील की है। छात्र नेता शीतल तिर्की और रवींद्र पासवान का कहना है कि 10 अगस्त का विधानसभा मार्च बहुत अहम और निर्णायक होने वाला है, जिसमें पूरे राज्य से करीब 50 हजार से 1 लाख छात्र शामिल होंगे। इस बीच, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ और झारखंड बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू ने भी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जाकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात की। छात्रों ने सरकार के सामने ये प्रमुख मांगें रखी हैं-14वीं जेपीएससी पीटी, JSSC CGL, JE और PGT जैसी विवादित परीक्षाओं को तुरंत कैंसिल किया जाए। भर्ती प्रक्रिया में धांधली और पेपर लीक के मामलों की निष्पक्ष CBI जांच हो। परीक्षा माफियाओं और इसमें शामिल एजेंसियों पर सख़्त से सख़्त कानूनी एक्शन लिया जाए। सभी कैटेगरी (UR, EWS, BC-I, BC-II, SC, ST) के कट-ऑफ मार्क्स और हरूक्क शीट पज़्लिक की जाएं। जेपीएससी-जेएसएससी के पूरे एग्जाम सिस्टम और काम करने के तरीके में बड़े स्तर पर सुधार किए जाएं। परीक्षा विवाद को सुलझाने के लिए झारखंड सरकार रविवार को प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ 6वें राउंड की बातचीत करेगी। इसके बाद ही सरकार कोई फाइनल फैसला लेगी। छात्रों से बात करने के लिए बनाई गई सरकारी कमेटी ने मुज़्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ करीब 4 घंटे तक मीटिंग की और उन्हें पिछली 5 बैठकों की पूरी रिपोर्ट दी। कमेटी की सदस्य और मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बताया कि उन्होंने छात्रों की सभी मांगों और उनके विचारों से मुज़्यमंत्री को पूरी तरह अपडेट कर दिया है।

नासिक में महसूस हुए 4.3 तीव्रता के झटके, मकानों की दीवारों में पड़ीं दरारें

नासिक ०९/०८ (संवाददाता): महाराष्ट्र के नासिक में हल्का भूकंप आने के बाद कई इलाकों में झटके महसूस किए गए जिससे जिले के कुछ स्थानों पर मकानों में दरारें पड़ गईं। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के अनुसार, शनिवार रात 10 बजे नासिक में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया। इसके बाद रविवार सुबह पांच बजकर 33 मिनट पर 3.3 तीव्रता का झटका महसूस किया गया।

अधिकारियों के अनुसार, भूकंपीय गतिविधि महाराष्ट्र-गुजरात सीमा के पास हाटगढ़ पर्वत श्रृंखला के निकट भनवड इलाके में पांच किलोमीटर की गहराई पर दर्ज की गई।

नासिक शहर के कुछ हिस्सों के अलावा जिले की सुरगाणा, कलवण, देवला, चांदवड, पेठ, दिंडोरी एवं निफाड तहसीलों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए और लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए।

जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि सुरगाणा तहसील के भादर और दिंडोरी तहसील के नानाशी में कुछ मकानों की दीवारों में दरारें पड़ गईं। उन्होंने बताया कि इस दौरान किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। उन्होंने बताया कि इलाके में बांधों का भी निरीक्षण किया गया, लेकिन उनमें कोई नुकसान नहीं पाया गया।

जिलाधिकारी आयुष प्रसाद ने कहा, ''लोगों को डरने की जरूरत नहीं है और न ही उन्हें किसी अफवाह पर विश्वास करना चाहिए। हालांकि, सभी को सतर्क रहना चाहिए और सुरक्षा संबंधी सावधानियां बरतनी चाहिए।'' इससे पहले जिले में 25 से 28 जुलाई के बीच और छह अगस्त को भी भूकंप के झटके दर्ज किए गए थे।

बंगाल में ममता बनर्जी के काफिले पर हमला, गाड़ी पर कीचड़ और पत्थर फेंकने का आरोप

कोलकाता ०९/०८ (संवाददाता): पश्चिम बंगाल की पूर्व मुज़्यमंत्री ममता बनर्जी को रविवार को नॉर्थ 24 परगना जिले में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। वह ज़ख़्म के एक दिवंगत कार्यकर्ता के घर जा रही थीं, तभी रास्ते में प्रदर्शनकारियों ने उनके खिलाफ चोर के नारे लगाए। आरोप है कि इस दौरान उनकी गाड़ी पर कीचड़ भी फेंका गया। यह घटना बिजपुर इलाके में हुई। जब ममता बनर्जी पार्टी के मृतक कार्यकर्ता के परिजनों से मिलने जा रही थीं, तभी प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और नारेबाजी शुरू कर दी। आपको बता दें कि इस ज़ख़्म कार्यकर्ता की मौत हालिसहर पुलिस की कस्टडी में बीमार पड़ने के बाद हुई थी। घटना के बाद पत्रकारों से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, मेरी गाड़ी पर पत्थर, जूते और कीचड़ फेंके गए।

यह मेरे खिलाफ एक सोची-समझी साजिश है। मैंने पुलिस को अपने आने की जानकारी पहले ही दे दी थी, फिर भी सुरक्षा के कोई पुख़्ता इंतजाम नहीं किए गए। पूरे पश्चिम बंगाल पर असामाजिक तत्वों का कब्ज़ा हो चुका है। दूसरी तरफ, प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ममता बनर्जी एक शांत इलाके में बेवजह अशांति पैदा करने आई थीं। इसी बात से नाराज होकर उन्होंने ममता बनर्जी के दौरे का कड़ा विरोध किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा गड़बड़ी के विरोध में विस के बाहर अनशन पर बैठे जयराम महतो

रांची ०९/०८ (संवाददाता): जेपीएससी-जेएसएससी समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी के खिलाफ छात्र पिछले 16 दिनों से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि, अभी तक सरकार की तरफ से उनकी मांगें नहीं मानी गई हैं। इसी के विरोध में डुमरी से विधायक जयराम महतो विधानसभा परिसर के बाहर एक दिन के अनशन पर बैठ गए हैं। इस दौरान वह पानी भी नहीं पिएंगे। उन्होंने समाज के हर वर्ग से छात्रों के समर्थन में अनशन करने की अपील की है। जयराम महतो ने कहा कि झारखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार धांधली के मामले सामने आ रहे हैं। इसमें सीटें बेचना, घर पर आंसर शीट लिखना और ओएमआर शीट खाली छोड़कर बाद में भरना जैसी बड़ी गड़बड़ियां शामिल हैं। उन्होंने मजदूर, वकील, व्यापारी और किसान संगठनों से भी कुछ समय निकालकर छात्रों के समर्थन में आगे आने और अनशन करने की अपील की है। जयराम महतो ने कहा कि सरकार को अच्छी तरह पता है कि इस धांधली के पीछे कौन लोग हैं। लाखों में सीटें बेची जा रही हैं और कोई छोटा अधिकारी अकेले इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। इसमें बड़े और ताकतवर लोग शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि अनशन के जरिए वह सरकार पर थोड़ा दबाव बनाना चाहते हैं। उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने और मुज़्यमंत्री से सीधे छात्रों से बात करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने छात्रों के विधानसभा घेराव के फैसले को अपना पूरा समर्थन दिया है।

लाठी-बंदूक से नहीं, बातचीत से निकलेगा हल, रांची में चल रहे छात्र आंदोलन पर बोले हेमंत सोरेन

रांची ०९/०८ (संवाददाता): रांची में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच झारखंड के मुज़्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली का विरोध कर रहे युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ न्याय दिलाने का वादा किया है। झारखंड आदिवासी दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि घर की समस्याओं का समाधान बातचीत से ही निकल सकता है, लाठी या बंदूक से नहीं। हथियार तो सीमा पर दुश्मनों का सामना करने के लिए होते हैं। उन्होंने छात्रों को आश्वस्त किया कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों को बज़्शा नहीं जाएगा। मुज़्यमंत्री ने बीजेपी और अन्य विरोधी दलों पर झूठ फैलाकर राज्य के युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए राज्य के माहौल को खराब करने और आंदोलन का राजनीतिकरण करने में लगे हैं। उन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए नीट पेपर लीक प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि वहां युवाओं पर लाठियां चलाई गईं और उन्हें देशद्रोही तक कहा गया, लेकिन झारखंड सरकार छात्रों पर बल प्रयोग करने के पक्ष में नहीं है। हेमंत सोरेन ने कहा कि युवाओं की चिंता उनकी अपनी चिंता है। उन्होंने कहा, हमने चोरी पकड़ी है और हम ही न्याय दिलाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से अपील की कि वे अपने आंदोलन के लिए किसी राजनीतिक दल का सहारा न लें, ज़्योंकि न्याय पाना उनका अधिकार है और सरकार इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन रविवार को 16वें दिन में प्रवेश कर गया, जिसमें 6 छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस बीच, रांची के राजकीय अतिथि गृह में सरकार और आंदोलनकारियों के प्रतिनिधियों के बीच छठे दौर की बातचीत हुई।

टर्बुलेंस का शिकार हुई एयर इंडिया का पायलट डोप टेस्ट में फेल

नयी दिल्ली ०९/०८ (संवाददाता): 4 अगस्त को टर्बुलेंस का शिकार हुई एयर इंडिया की फुकेट-दिल्ली ज़्लाइट को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। सूत्रों के अनुसार, लैंडिंग के बाद जब ज़्लाइट के कैप्टन का डोप टेस्ट कराया गया, तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। एयरलाइन ने इस खबर की न तो पुष्टि की है और न ही इससे इनकार किया है। एयर इंडिया के प्रवक्ता का कहना है कि नियमों के तहत पायलटों का स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था, लेकिन इसके नतीजे उनके साथ शेयर नहीं किए गए हैं, इसलिए वे इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं कर सकते।

इस ज़्लाइट में कुल 145 लोग सवार थे। ओडिशा के पास अचानक विमान को टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा, जिससे प्लेन अचानक 300 फीट नीचे आ गिरा। दिल्ली पहुंचने के बाद 13 यात्रियों और 4 ज़्रू मेंबर्स को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। एयरलाइन का कहना है कि वे नियमों के तहत ज़्रू मेंबर्स का रेगुलर ड्रग टेस्ट करते हैं और जांच अधिकारियों का पूरा सहयोग कर रहे हैं। विमानन नियामक DGCA इस पूरी घटना की हर पहलू से जांच कर रहा है। जांच में यह देखा जा रहा है कि टर्बुलेंस को सही तरीके से संभाला गया या नहीं, झटकों से कोई तकनीकी खराबी (जैसे हाइड्रोलिक फेलियर) तो नहीं हुई, और ज़्या विमान को दिल्ली लाने के बजाय वाराणसी या लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग करानी चाहिए थी प्रोटोकॉल के तहत जांच पूरी होने तक ज़्लाइट ज़्रू को उड़ानों से हटा दिया गया है। ष्ठत्रष्ट के नियमों के मुताबिक, अगर कोई पायलट पहली बार डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाता है, तो उसे रिहैबिलिटेशन के लिए भेजा जाता है और रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही वापस ड्यूटी मिलती है। दूसरी बार पॉजिटिव आने पर लाइसेंस 3 साल के लिए सस्पेंड और तीसरी बार में लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाता है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन के नियमों के अनुसार, कोई भी पायलट ऐसे किसी भी नशीले या दिमाग पर असर डालने वाले पदार्थ के प्रभाव में विमान नहीं

अमरनाथ यात्रा का अंतिम चरण: छड़ी मुबारक यात्रा की सूची जारी, २८ अगस्त को होगा समापन

नयी दिल्ली ०९/०८ (संवाददाता): अमरनाथ यात्रा का मुज़्य आकर्षण अब भगवान शिव की पवित्र छड़ी 'छड़ी मुबारक' की अनुष्ठानिक यात्रा होगी। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि यह यात्रा बृहस्पतिवार से शुरू होगी और दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित अमरनाथ गुफा तक जाएगी। 'छड़ी मुबारक' को 12 अगस्त को यहां स्थित ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर और 13 अगस्त को शारिका भवानी मंदिर ले जाया जाएगा। इसके बाद 15 अगस्त को श्री अमरेश्वर मंदिर दशनामी अखाड़ा श्रीनगर में 'छड़ी स्थापना' के लिए अनुष्ठान किया जाएगा। महंत दीपेंद्री गिरि ने कहा, नाग पंचमी के अवसर पर 17 अगस्त को दशनामी अखाड़ा श्रीनगर में पारंपरिक छड़ी-पूजन किया जाएगा। 22 अगस्त को पवित्र छड़ी तीर्थयात्रा के मुज़्य मार्ग पर रवाना होगी और इसे स्वामी अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तक ले जाया जाएगा, जहां 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर पूजा-अर्चना और दर्शन किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 22 और 23 अगस्त को पहलगाम में, 24 अगस्त को चंदनवारी में, 25 अगस्त को शेषनाग में तथा 26 और 27 अगस्त को क्रमश: पंचतरणी में रात्रि विश्राम होगा। इससे पहले शनिवार को अधिकारियों ने अमरनाथ गुफा जाने वाले दोनों मार्गों की मरज़्मत के लिए अमरनाथ यात्रा को निलंबित किए जाने की घोषणा की थी। कश्मीर के संभाग आयुक्त अंशुल गर्ग ने कहा, ''यात्रा नौ अगस्त, 2026 से दोनों मार्गों पर निलंबित रहेगी। छड़ी मुबारक पारंपरिक पहलगाम मार्ग से जाएगी और 28 अगस्त को अमरनाथ यात्रा-2026 का समापन होगा।''

उन्होंने कहा कि 57 दिन चलने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा इस वर्ष तीन जुलाई को शुरू हुई थी और 28 अगस्त को 'छड़ी मुबारक' के साथ संपन्न होगी। उन्होंने बताया कि यह यात्रा अनंतनाग जिले के चंदनवाड़ी मार्ग और गांदरबल जिले के बालटाल मार्गों से एक साथ शुरू हुई थी। गर्ग ने कहा, अब तक चार लाख 80 हजार से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। हालांकि, हाल में हुई बारिश के कारण यात्रा मार्ग के संवेदनशील हिस्सों में मरज़्मत और रखरखाव की जरूरत महसूस हुई है। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) इन मार्गों की मरज़्मत का काम कर रहा है। इसके अलावा, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले कुछ दिनों में खराब मौसम की आशंका जताई है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से अपील की कि अपनी सुरक्षा और यात्रा को सुचारु रूप से जारी रखने के लिए वे सक्षम अधिकारियों की ओर से समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।

विविध समाचार

बंगाल से रोजाना ५ से १० हजार घुसपैठिए बांग्लादेश जा रहे, होल्डिंग सेंटर की संख्या भी बढ़ी

कोलकाता ०९/०८ (संवाददाता): पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ अब तक का सबसे व्यापक अभियान चल रहा है और इसके नतीजे जमीन पर साफ दिखाई देने लगे हैं। राज्यभर में संदिग्ध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान, सत्यापन और वापसी की प्रक्रिया को तेज करते हुए होल्डिंग सेंटरों की संज़्या महज एक सप्ताह के भीतर बढ़कर 11 हो गई है। इन केंद्रों में फिलहाल साढ़े तीन सौ से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिक रखे गए हैं, जिनमें सबसे अधिक संज़्या उज़र 24 परगना के बसीरहाट क्षेत्र में है। इसके साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठियों की ओर से बना लिये गये अवैध ढांचों पर बुलडोजर की कार्रवाई भी लगातार चल रही है।

यह अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसांज़्यिक संतुलन की रक्षा का एक निर्णायक कदम माना जा रहा है। विशेष रूप से बसीरहाट, बनगांव, मालदा, मुर्शिदाबाद और नदिया जैसे सीमावर्ती जिलों में निगरानी और पहचान अभियान को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचा दिया गया है। बसीरहाट उपमंडल के टेटुलिया, चारघाट और मेडिया में हाल ही में शुरू हुए नए केंद्रों में सैकड़ों संदिग्ध घुसपैठियों को रखा गया है। जांच में यह भी सामने आया है कि अनेक घुसपैठियों ने रिश्वत देकर पहचान पत्र, आधार और मतदाता पहचान पत्र जैसे दस्तावेज हासिल कर लिए थे। लेकिन जब सुरक्षा एजेंसियों के सामने उनकी जांच हुई तो उनके पास बांग्लादेश सरकार द्वारा जारी पहचान दस्तावेज ही मिले। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि वर्षों से संगठित तरीके से अवैध घुसपैठ और दस्तावेज जालसाजी का खेल चल रहा था। अब सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की परत दर परत जांच कर रही हैं।पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पकड़े गए लोगों ने स्वीकार किया कि एजेंट सीमा पर गश्त के बीच के समय का फायदा उठाकर उन्हें भारत में प्रवेश कराते थे। प्रति व्यक्ति सात हजार से बीस हजार रुपये तक वसूले जाते थे। इसके बाद फर्जी दस्तावेज तैयार कराए जाते और उन्हें राजमिस्त्री, दिहाड़ी मजदूर या घरेलू कामगार के रूप में विभिन्न इलाकों में बसाया जाता था। यह केवल घुसपैठ नहीं, बल्कि एक संगठित और सुनियोजित तंत्र का संकेत है, जिस पर अब करारा प्रहार हो रहा है। इसी बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कहा कि पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद स्थिति तेजी से बदली है। उन्होंने कहा कि जहां पहले प्रतिदिन हजारों घुसपैठिए राज्य में प्रवेश करते थे, वहीं अब 5 से 10 हजार लोग प्रतिदिन वापस लौट रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जनसांज़्यिक परिवर्तन आयोग जनसंज़्या संरचना में बदलाव और उसके कारणों का अध्ययन करेगा तथा आवश्यक कानूनी उपायों पर विचार करेगा। देखा जाये तो इस पूरे अभियान के बीच मुज़्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी की सरकार की नीतियों की व्यापक चर्चा हो रही है। सीमावर्ती जिलों में तेजी से हो रही कार्रवाई, नए होल्डिंग सेंटरों की स्थापना, पहचान सत्यापन अभियान और सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय ने यह संकेत दिया है कि अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर सरकार किसी भी तरह की ढिलाई के पक्ष में नहीं है। वर्षों से लंबित इस समस्या पर निर्णायक कदम उठाने का प्रयास दिखाई दे रहा है। देखा जाये तो अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए यह एक सज़्त चेतावनी है। फर्जी दस्तावेज, एजेंटों के नेटवर्क और पहचान छिपाने की पुरानी तरकीबें अब काम नहीं आने वाली हैं। कानून का शिकंजा लगातार कस रहा है और हर स्तर पर सत्यापन अभियान चल रहा है। जो लोग अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं, उनके लिए सबसे उचित विकल्प यही है कि वे कानूनी प्रक्रिया का सज़्मान करें और स्वेच्छा से अपने देश लौट जाएं। बहरहाल, इसमें कोई दो राय नहीं कि पश्चिम बंगाल में चल रहा यह अभियान राष्ट्रीय हित, कानून के शासन और जनसांज़्यिक संतुलन की रक्षा का भी प्रश्न है। आने वाले दिनों में यह कार्रवाई और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं, जिससे साफ है कि अवैध घुसपैठ के खिलाफ अब निर्णायक दौर शुरू हो चुका है।

बंगाल भाजपा अध्यक्ष का दावा, टीएमसी के कई विधायक व सांसद आना चाहते हैं, पर भी दरवाजा बंद

कोलकाता ०९/०८ (संवाददाता): पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने स्पष्ट किया है कि पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेताओं को शामिल करने में कोई जल्दबाजी नहीं कर रही है। उनका दावा है कि राज्य में भाजपा की जीत के बाद टीएमसी के कई मौजूदा सांसद और विधायक भाजपा में शामिल होने के इच्छुक हैं, लेकिन पार्टी ने फिलहाल ऐसे नेताओं के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। पीटीआई समाचार एजेंसी को दिए एक साक्षात्कार में भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा ने अपने दम पर निर्णायक जनादेश प्राप्त किया है, इसलिए वह प्रतिद्वंद्वी दलों के नेताओं को समायोजित करने के लिए बाध्य नहीं है और उसने 2021 के विधानसभा चुनावों से पहले हुए बड़े पैमाने पर दलबदल से सबक लिया है।

किसी नेता का नाम लिए बिना या आंकड़े बताए बिना उन्होंने कहा कि कई टीएमसी सांसद और विधायक हमारे साथ जुड़ने को तैयार हैं, लेकिन मैं आंकड़ों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि भाजपा को राज्य में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अब बाहरी नेताओं की जरूरत नहीं है। अभी दरवाजा बंद है। हमें चुनाव जीतने के लिए अब किसी टीएमसी नेता की जरूरत नहीं है। हम अपने दम पर जीते हैं।

हालांकि, भट्टाचार्य ने कुछ शर्तों के तहत भविष्य में नेताओं को शामिल करने की संभावना को खुला रखा। उन्होंने कहा कि राजनीति में दो और दो हमेशा चार नहीं होते; हम किसी भी दागी नेता के लिए अपने दरवाजे नहीं खोलेंगेž यह फैसला सामूहिक होगा, किसी एक व्यक्ति का नहीं। उन्होंने आगे कहा कि भले ही भाजपा भविष्य में नए नेताओं को शामिल करने पर विचार करे, लेकिन भ्रष्टाचार, भर्ती घोटालों में संलिप्तता या टीएमसी के कथित सिंडिकेट नेटवर्क से जुड़े नेताओं का स्वागत नहीं किया जाएगा।

सज़ाधारी पार्टी के विभिन्न वर्गों के बीच भेदभाव करने के आरोपों को खारिज करते हुए भट्टाचार्य ने कहा कि मैंने कभी यह नहीं कहा कि कोई टीएमसी अच्छी है या कोई टीएमसी बुरी। टीएमसी और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि टीएमसी से जुड़े कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जो उनके द्वारा वर्णित भ्रष्ट तंत्र से बाहर रहे और उन्होंने चुनाव में भाजपा का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग हैं जो टीएमसी का हिस्सा थे लेकिन उस भ्रष्ट व्यवस्था से बाहर रहे। उनमें से कई लोगों ने हमें वोट दिया।

राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, विश्व गुरु हैं पर एक भी परीक्षा ठीक से नहीं करा सकते

नयी दिल्ली ०९/०८ (संवाददाता): कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार खुद को विश्वगुरु बताते हुए भी एक भी परीक्षा ठीक से आयोजित करने में असमर्थ रही है। उनकी यह टिप्पणी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीईसीए) द्वारा यह बताए जाने के बाद आई है कि तकनीकी खराबी के कारण शनिवार को कुछ केंद्रों पर स्नातक डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित सीयूईटी-यूजी 2026 परीक्षा में देरी हुई।

ङ्ग पर हिंदी में लिखे एक पोस्ट में गांधी ने कहा कि ह्श्वश्वञ्ज, ष्टक्रस्श्व, स्स्ष्ट और आज ष्टश्वञ्ज। चार परीक्षाएं। एक करोड़ छात्र। इनमें से एक भी परीक्षा ईमानदारी से नहीं कराई जा सकी। गांधी ने कहा कि खुद को %विश्वगुरु% कहते हैं, लेकिन देश में एक भी परीक्षा कराने में असमर्थ हैं - मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए कहा कि जिस पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं, वही पीढ़ी आपको जवाबदेह ठहराएगी। गांधी ने शुक्रवार को कहा था कि ष्टक्रस्श्व की विफलता पर मोदी की चुप्पी और शिक्षा मंत्री के खिलाफ कार्रवाई न करना यह दर्शाता है कि उन्हें केवल अपनी सरकार के अस्तित्व की चिंता है, लाखों छात्रों के भविष्य की नहीं।

कांग्रेस नेता ने उन छात्रों के साथ अपनी पिछली बातचीत का एक वीडियो भी साझा किया था, जिन्होंने नीईटी परीक्षा दी थी और पेपर लीक के मद्देनजर परीक्षा प्रणाली को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की थीं।

योगी आदित्यनाथ ने में कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा, सुरक्षा बनाए रखने के निर्देश दिए

मेरठ ०९/०८ (संवाददाता): उज़र प्रदेश के मुज़्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कांवड़ यात्रा में शामिल शिव भक्तों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और कांवड़ यात्रियों की नियमित सुरक्षा, सज़्मान, सुविधा आदि की समुचित व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। पूरे कांवड़ मार्ग पर हेलिकॉप्टर से भी शिवभक्तों पर पुष्पवर्षा की गई। आयोजन स्थल पर पहुंचने से पहले मुज़्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हेलिकॉप्टर से कांवड़ यात्रा का अवलोकन किया। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए भक्तों की श्रद्धा को नमन किया और प्रशासनिक अधिकारियों को कांवड़ यात्रियों की नियमित सुरक्षा, सज़्मान, सुविधा आदि की समुचित व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। मेरठ के मोदीपुरम क्षेत्र में दुल्हेड़ा पुलिस चौकी के निकट बनाए गए मंच से योगी आदित्यनाथ ने 'बोल बम' और 'हर-हर महादेव' के जयकारों के बीच कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। इस अवसर पर उनके साथ रामानंद सागर के धारावाहिक 'रामायण' में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल, उज़र प्रदेश सरकार में मंत्री सोमेंद्र तोमर समेत कई प्रमुख लोग मौजूद थे।

गोविल, मेरठ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं। योगी ने इस मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, सभी जनप्रतिनिधियों, सामाजिक और धार्मिक संगठनों का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ कांवड़ियों की सुविधाओं का ध्यान रखा है। सावन में कांवड़ यात्रा का हिस्सा बन रहे सभी शिव भक्तों का अभिनंदन करता हूं और उनकी इस यात्रा के लिए देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करता हूं कि वे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मुज़्यमंत्री ने कहा, प्रदेश और देश में सुख, शांति, समृद्धि और सौहार्द का माहौल बनाने के लिए देवाधिदेव महादेव की कृपा बनी रहे, इसी भावना के साथ आज मुझे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर मिला है।卐 उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा अपने समापन की ओर बढ़ रही है।

हरिद्वार में हर की पैड़ी से गंगाजल लेकर शिवभक्त अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हुए विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हैं। उन्होंने कहा, 卐मेरा मानना है कि सावन की शिवरात्रि तक गाजियाबाद से लेकर हरिद्वार के बीच चार से साढ़े चार करोड़ श्रद्धालु और शिवभक्त इस कांवड़ यात्रा में गंगाजल लेकर शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे।卐 मुज़्यमंत्री ने कहा, आज मुजफ़्फरनगर के शिव चौक पर भारी भीड़ है। अभी मेरठ में मुझे शिवभक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करने का अवसर मिला है।

मेरठ के हमारे सभी जनप्रतिनिधि इस अवसर पर मेरे साथ यहां मौजूद हैं। योगी ने कहा कि मेरठ के प्रसिद्ध बाबा औघड़नाथ मंदिर, गाजियाबाद के बाबा दूधेश्वरनाथ मंदिर और बागपत के पुरा महादेव मंदिर समेत पश्चिमी उज़र प्रदेश के दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से आने वाले शिवभक्त इस यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं। उन्होंने कहा, 卐पूरी श्रद्धा, उत्साह और उमंग के साथ यात्रा में शामिल होने आए कांवड़ियों का प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुज़्यमंत्री ने कांवड़ियों के राष्ट्र के प्रति समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि जात-पात, प्रांत और क्षेत्रीयता की सीमाओं से ऊपर उठकर शिवत्व की भावना से एकाकार होने के लिए यह यात्रा उत्साह और उमंग का वातावरण पैदा कर रही है। प्रशासनिक तैयारियों और व्यवस्थाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, प्रशासन ने उच्च स्तर की व्यवस्था की है.

भोपाल में अवैध कफ सिरप बनाने वाली यूनिट का किया भंडाफोड़

भोपाल ०९/०८ (संवाददाता):: अवैध और नशीली दवाओं के निर्माण व तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, मध्य प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (स्ञ्जस्न) ने भोपाल के गांधी नगर इलाके में एक रिहायशी मकान से संचालित हो रही अवैध कफ सिरप बनाने वाली फैज़्ट्री का पर्दाफाश किया है। इस औचक कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में नशीला कफ सिरप, निर्माण उपकरण और पैकेजिंग सामग्री ज़ज़्त की गई है। अधिकारियों ने बताया कि यह छापामार कार्रवाई गांधी नगर स्थित डोबरा पटेल सिटी कॉलोनी के एक मकान में की गई। सुरक्षा बलों को इस इलाके में नशीले कफ सिरप के अवैध निर्माण और उसकी गुप्त सप्लाई के संबंध में एक पुज़्ता खुफिया जानकारी मिली थी।

स्ञ्जस्न के डिप्टी इंस्पेज़्टर जनरल राहुल लोढ़ा के मुताबिक, यह ऑपरेशन आधी रात के करीब शुरू हुआ और सुबह लगभग 3 बजे तक चला। यह छापा स्ञ्जस्न के जवानों और ड्रग विभाग के अधिकारियों ने मिलकर मारा। तलाशी के दौरान, जांचकर्ताओं को कफ सिरप के कार्टन, बोतलें और मशीनें बड़ी मात्रा में मिलीं। आरोप है कि इन मशीनों का इस्तेमाल नाम के एक बिना लाइसेंस वाले कफ सिरप ब्रांड को बनाने और पैक करने के लिए किया जा रहा था। अधिकारियों का अनुमान है कि ज़ज़्त किए गए सामान और उपकरणों की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपये है।

स्ञ्जस्न ने इस मामले में सात लोगों को गिरज़्तार किया है, जिनमें तीन नाबालिग भी शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, और भी गिरज़्तारियां हो सकती हैं। ज़ज़्त किए गए कफ सिरप के सैंपल लैब टेस्ट के लिए भेजे गए हैं, ताकि उसकी बनावट का पता चल सके और यह भी पता लगाया जा सके कि उसमें कोई प्रतिबंधित या नियंत्रित पदार्थ तो नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि स्ञ्जस्न को कुछ समय से गांधी नगर इलाके से नशीले कफ सिरप के अवैध निर्माण और वितरण के बारे में जानकारी मिल रही थी। इन्हीं जानकारियों के आधार पर एक खास ऑपरेशन की योजना बनाई गई और उसे अंजाम दिया गया।

सूत्रों ने बताया कि इस छापे के बारे में स्थानीय पुलिस थाने को पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी स्ञ्जस्न के वरिष्ठ अधिकारी कर रहे थे।

जांचकर्ता अब कफ सिरप बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही, वे उस वितरण नेटवर्क की भी पहचान करने में जुटे हैं, जिसके ज़रिए कथित तौर पर इस कफ सिरप की सप्लाई की जा रही थी। जिस मकान में यह ऑपरेशन किया गया, वह कथित तौर पर मालवीय नाम के किसी व्यक्ति का है। हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि वे मकान मालिक से संपर्क नहीं कर पाए हैं और वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि ज़्या इस कथित अवैध काम में मकान मालिक की भी कोई भूमिका थी। स्ञ्जस्न अधिकारियों ने बताया कि एक मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि ज़्या ज़ज़्त की गई कफ़ सिरप की सप्लाई दूसरे ज़िलों और राज्यों में भी की जा रही थी।

केरल में वंदे मारतम पर घमासान, राज्यपाल नाराज, सीएम बोले अनिवार्य नहीं

तिरुवनंतपुरम ०९/०८ (संवाददाता): केरल के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने शुक्रवार को अपने नीतिगत भाषण से पहले राज्य विधानसभा में वंदे मातरम का पूर्ण गायन न होने पर नाराजगी व्यक्त की, जबकि मुज़्यमंत्री वी डी सतीशान ने कहा कि राष्ट्रगान का पूर्ण पाठ अनिवार्य नहीं है। केरल विधानसभा में राज्यपाल द्वारा यूडीएफ सरकार के नीतिगत भाषण को पढ़ने से पहले और बाद में केरल पुलिस बैंड ने वंदे मातरम के केवल पहले दो छंद बजाए, जबकि लोकसभा ने निर्देश दिया था कि राज्यपाल की उपस्थिति में वंदे मातरम पूर्ण रूप से गाया जाए।राजेंद्र अर्लेकर ने दावा किया कि राज्यपाल के ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने पर उचित प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने विधानसभा अध्यक्ष से बात की है। देखते हैं आगे ज़्या होता है।

मुज़्यमंत्री सतीशन ने कहा कि ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है जो वंदे मातरम को पूर्ण रूप से गाने को अनिवार्य बनाता हो। उन्होंने कहा कि संसद ने इस संबंध में कोई कानून नहीं बनाया है। अगर राज्यपाल को कोई शिकायत है, तो मैं उनसे इस बारे में बात करूंगा। भाजपा विधायक वी मुरलीधरन ने इस कदम को लोकभवन और राज्यपाल का अपमान बताया और यूडीएफ सरकार पर सीपीआई (एम) और जमात-ए-इस्लामी जैसी पार्टियों के दबाव में झुकने का आरोप लगाया। विधानसभा में विपक्ष के नेता पिनारयी विजयन ने भी राज्य सरकार के राष्ट्रगान को पूरी तरह से न बजाने या न गाने के फैसले का समर्थन करते हुए इसे आरएसएस का एजेंडा बताया।

कलिंग समाचार
THE KALINGA SAMACHAR
(A Hindi Daily News Paper)
PUBLISHED FROM ODISHA, JHARKHAND & CHATTISHGARH
FOR NEWS AND ADVERTISEMENT CONTACT
AT: QRS. NO. B/204, SECTOR-16
ROURKELA, PH. 0661-2646999
PRAKASH KUMAR DHAL (EDITOR)
E-mail: thekalingasamachar@gmail.com

विविध समाचार

आरओ का पानी खतरनाक...

हमें कुछ मिले या न मिले पर शरीर को पानी जरूर मिलना चाहिए। अगर पानी आरओ का हो तो, क्या बात है, लेकिन क्या वास्तव में हम आरओ के पानी को शुद्ध पानी मान सकते है? जवाब आता है बिल्कुल नहीं। यह जवाब विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से दिया गया है। डब्ल्यूएचओ ने बताया है कि आरओ के पानी के लगातार सेवन से हृदय संबंधी विकार, थकान, कमजोरी, मांसपेशियों में ऐंठन, सिरदर्द आदि दुष्प्रभाव पाए गए हैं। यह कई शोधों के बाद पता चला है कि इसकी वजह से कैल्शियम और मैग्नीशियम पानी से पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं जो कि शारीरिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। वैज्ञानिकों के अनुसार मानव शरीर 500 टीडीएस तक सहन करने की क्षमता रखता है परंतु आरओ में 18 से 25 टीडीएस तक पानी की शुद्धता होती है जो कि नुकसानदायक है। इसके विकल्प में क्लोरीन को रखा जा सकता है जिसमें लागत भी कम होती है एवं पानी के आवश्यक तत्व भी सुरक्षित रहते हैं। जिससे मानव का शारीरिक विकास अवरुद्ध नहीं होता। जहां एक तरफ एशिया और यूरोप के कई देश आरओ पर प्रतिबंध लगा चुके हैं वहीं भारत में आरओ की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और कई विदेशी कंपनियों ने यहां पर अपना बड़ा बाजार बना लिया है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना और जागरूक करना जरूरी है। अतः अब शुद्ध पानी के लिए नए अधिकारों की जरूरत है। याद रखें की लंबे समय तक आरओ का पानी लगातार पीने से शरीर कमजोर और बीमारियों का घर बन जाता है। अतः प्राकृतिक यानी खनीज युक्त पानी परंपरागत तरीकों से साफ कर पीना हितकर है।

ऑनलाइन पेमेंट और भी आसान...

गूगल ने क्रोम का लेटेस्ट वर्जन रिलीज किया है, जिसका सबसे खास फीचर गूगल पे है और साथ ही परफॉरमेंस में सुधार हुआ है। क्रोम में गूगल पे फीचर एड करने से कंपनी ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह सुविधा प्रदान करवाना चाहती है। गूगल ने वैब स्टैंडर्ड्स पर पेमेंट्स को आसान बनाने के लिए एंड्रायड पे को क्रोम में एड किया है। फिलहाल आईओएस, डिवाइसेस में इस फीचर के आने की कोई जानकारी नहीं है। एंड्रॉयड यूजर्स कुछ ही समय में ऑनलाइन पेमेंट्स को संभव कर सकता है। गूगल ने अपने ब्लॉग में यह भी लिखा कि एंड्रॉयड के लिए क्रोम का नया वर्जन 15 प्रतिशत तेज होगा। नए अपडेट से क्रोम ज्यादा बैटरी की बचत भी करेगा। गूगल प्ले स्टोर पर गूगल क्रोम की अपडेट को फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है।

नया ब्लूटूथ स्मार्ट बल्ब...

घर को आकर्षक और सुंदर बनाने में सबसे ज्यादा लाइटनिंग का यूज होता है। इस बात पर ध्यान देते हुए एसएमएफएक्स कंपनी ने नया ब्लूटूथ स्मार्ट बल्ब विकसित किया है जो 16 मिलियन रंगों से आपके ऑफ हुए मूड को भी पूरी तरह से बदल देगा। यह स्मार्ट बल्ब मौजूदा सॉकेट से आसानी से चलाया जा सकता है। साधारण बल्ब से 10 प्रतिशत ज्यादा एनर्जी सेविंग होने के साथ-साथ यह 40,000 घंटों की लाइफ भी देगा। इसमें आप लाइट्स को समय-समय पर शेड्यूल कर सकते हैं और एप की मदद से कंट्रोल भी कर सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इसे करीब 2664 रुपए कीमत में बिक्री के लिए उपलब्ध किया जाएगा।

कम समय में चार्ज होगी नई बैटरी...

निजी क्षेत्र की ग्रीनविजन टैक्नालॉजीज ने पर्यावरण अनुकूल उपकरणों को बढ़ावा देते हुए कम समय में चार्ज होने वाली और रखरखाव में आसान 'जेल प्रौद्योगिकी' आधारित बैटरी विकसित की है जो कि ई-रिक्शा के लिए उपयोगी साबित होगी। दावा है कि एक तरफ जहां यह बैटरी जल्दी चार्ज होती है वहीं दूसरी तरफ इसका रख-रखाव काफी आसान है क्योंकि इसमें पानी यानी डीएम वाटर डालने की आवश्यकता नहीं है। जेल तकनीक आधारित इस बैटरी का नाम 'बायेजर' रखा गया है। सामान्य बैटरी के मुकाबले इनका वजन हल्का और आकार छोटा है। इसे 6 घंटे में पूरी तरह चार्ज किया जा सकता है जबकि अन्य बैटरियों को चार्ज करने में 8 घंटे का समय लगता है। इसके लिए विशेष तौर पर तैयार चार्जर भी बनाया गया है जिससे इन बैटरी की उम्र और भी बढ़ जाती है। बार-बार चार्ज कर इसका 40,000 किलोमीटर तक उपयोग किया जा सकता है।

भविष्य में आपके घर में टेबल पर मौजूद सजावटी सामग्रियों के बीच आपकी 'शेपीज' यानी आपकी शेप का पुतला हो सकता है। सेल्फी को स्मार्टफोन में ही देख सकते हैं। लेकिन, अब 3डी सेल्फी का जमाना आने वाला है। इस थ्रीडी सेल्फी को आप एक छोटे पुतले की भांति अपने साथ रख सकते हैं।

अब बनवाएं अपना 3डी पुतला...

सेल्फी का क्रेज अभी कम भी नहीं हुआ है कि तेजी से नए आयाम लेती तकनीक की दुनिया में फोटोग्राफी के लिए एक नये फॉर्मेट का चलन शुरू हो गया है। डिजिटल कैमरा और स्मार्टफोन ने फोटोग्राफी की दुनिया को ऐसे बदला कि फोटो स्टूडियो का क्रेज कम हो गया। अब 3डी प्रिंटर तकनीक इसमें नया बदलाव ला रही है। आने वाले समय में लोगों का रुझान ऐसे स्टूडियो की ओर बढ़ सकता है, जहां वे छोटे आकार के खुद के 3डी पुतले बनवा सकते हैं। सेल्फी खींचने और उसे डिजिटल फॉर्मेट में सुरक्षित रखने का मौजूदा ट्रेंड निकट जल्द ही बदल सकता है। दक्षिण कोरिया अब फोटोग्राफी को सेल्फी और डिजिटल प्रारूप में सुरक्षित रखने से आगे 3डी प्रिंटिंग के दौर में ले जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, सियोल में कई थ्रीडी फोटो स्टूडियो खुल चुके हैं, जहां एक छोटे पुतले के रूप में आप अपनी या बच्चों की 3डी प्रिंटिंग हासिल कर सकते हैं। फिलहाल इसकी कीमत ज्यादा है, इसलिए पैसे वाले लोग ही यहां पहुंचते हैं, लेकिन भविष्य में इसकी कीमत कम होने पर यह आम लोगों की पहुंच से बाहर नहीं रहेगा।

एक साथ 100 कैमरे

अपना 3डी पुतला बनवाने की चाहत रखने वाले इन स्टूडियो में बीच में बने एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं, जिसके चारों ओर करीब 100 कैमरे लगे हैं। ये सभी कैमरे अनेक एंगल से एक साथ आपकी 2डी तस्वीर खींचते हैं, जिन्हें सियोल की एक खास फैक्टरी में भेजा जाता है। इस फैक्टरी में 3डी प्रिंटर के लिए बनाए गए खास कंप्यूटर प्रोग्राम्स के दिशा-निर्देशों के तहत इसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है ।

हजार लेयर में इमेज

ट्रांसफॉर्म के बाद 3डी प्रिंटर जिप्सम पाउडर की करीब 1,000 लेयर में आपकी उस इमेज को गढ़ता है, 2डी तस्वीरें लेते वक्त इसमें वह उन सभी छोटी-से-छोटी चीजों को शामिल करता है, ताकि वह बिल्कुल असली की तरह दिखे। हालांकि, इस फिगर यानी पुतले का आकार बहुत छोटा होता है ।

99 डॉलर में पांच सेमी

इस तरह बनाए जानेवाले 3डी पुतलों की कीमत 99 डॉलर से 299 डॉलर तक है। सबसे छोटा आकार पांच सेंटीमीटर है, जिसकी कीमत 99 डॉलर है, जबकि सबसे 30 सेंटीमीटर आकार के पुतले की कीमत 299 डॉलर है। एक रिपोर्ट में एशियाई देशों में फिलहाल इस नई तकनीक को दक्षिण कोरिया तक ही सीमित बताया गया है, लेकिन जल्द ही पूरी दुनिया में इसके प्रसार की उम्मीद जताई गई है। हालांकि, कई अन्य रिपोर्ट बताती हैं कि भारत समेत कई देशों में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है ।

'सेल्फी' के बाद 'शेपीज'

भविष्य में आपके घर में टेबल पर मौजूद सजावटी सामग्रियों के बीच आपकी 'शेपीज' यानी आपकी शेप का पुतला हो सकता है। 'ब्लूमबर्ग टेक्नोलॉजी' के मुताबिक, लन्दनबर्ग आधारित कंपनी 'आर्टेक' ने सितंबर, 2014 में पहली बार '3डी बॉडी स्कैनिंग बूथ' का डिजाइन तैयार कर ड्रेस समेत पूरे शरीर की इमेज स्कैनिंग करके 3डी प्रिंट के छोटे प्रतिरूप में मुहैया कराया था। कैलिफोर्निया के पालो आल्टो में आर्टेक के शोरूम में यह तकनीक प्रदर्शित की गई थी। ग्राहकों को यहां पांच इंच का पुतला दिया जाता है। फिगर बनाने वाले इस आइडिया को फिलहाल 'शेपीज' या '3डी सेल्फीज' नाम दिया गया है ।

ऑनलाइन ऑर्डर

सेल्फी को स्मार्टफोन में ही देख सकते हैं। लेकिन, अब 3डी सेल्फी का जमाना आने वाला है। इस थ्रीडी सेल्फी को आप एक छोटे पुतले की भांति अपने साथ रख सकते हैं। 'माय3डीसेल्फी डॉट कॉम' इसके लिए बाकायदा ऑर्डर हासिल करता है।

पांच मिनट में 3डी मॉडल

आर्टेक शेपिफाई बूथ 3डी बॉडी स्कैनिंग और सेल्फी बनाने वाली ऑटोमेटेड मशीन है। महज 12 सेकेंड में ग्राहक की स्कैनिंग करके ऑटोमेटिक तरीके से पांच मिनट में 3डी मॉडल तैयार हो जाता है और कुछ दिनों में पूरी तरह तैयार करके इसे ग्राहक को भेज दिया जाता है। इस बूथ में प्रति घंटे 10 लोगों की स्कैनिंग की जा सकती है।

भारत में भी शुरुआत

हैदराबाद की एक फर्म '3डी स्कैयर' ने भी ऐसी एक शुरुआत की है। इसकी वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, 3डी प्रिंटिंग के जरिए पुतले बनाने का काम यह चार चरणों में पूरा करता है। पहले चरण में यह पूरे शरीर की फोटोग्राफिक तकनीक के जरिए तस्वीर की 3डी स्कैनिंग की जाती है। स्कैनिंग से हासिल किए गए 3डी डाटा को संबंधित 3डी सॉफ्टवेयर में एडिट करता है। कलर 3डी प्रिंटर में इसे प्रिंट किया जाता है। तैयार हुए प्रोडक्ट यानी पुतले पर चिपके अतिरिक्त पाउडर को हटाया जाता है और उस पर ग्लू चिपकाया जाता है।

क्लोन मी का 3डी प्रोडक्ट

यह 3डी सेल्फी से क्लोन बनाने वाली एक कंपनी है, जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और उत्तम कोटि की शिल्पकारी के जरिए 3डी फिगर तैयार करती है। यह कंपनी पांच चरणों में 3डी फिगर बनाती है। इच्छुक लोगों को सबसे पहले शोरूम आना होता है या फिर आप ऑनलाइन अपनी तस्वीर भेज सकते हैं। इसके प्रधान कार्यालय में स्कैनिंग को अंतिम रूप देते हुए उसकी गुणवत्ता बढ़ाई जाती है। 3डी फिगर तैयार होने के बाद शिल्पकारों द्वारा साज-सज्जा करते हुए इसे अंतिम स्वरूप प्रदान किया जाता है इसे रिफाइनमेंट कहते हैं।

स्कैबीज क्या है

इसके लक्षण और उपचार

स्कैबीज घुन से होने वाला खुजली वाला त्वचा का संक्रमण है। इसके अंडो और मल से होने वाले एलर्जिक प्रतिक्रिया के कारण रोगी को दाने या मुंहासे होते हैं। इसका उपचार आसानी से हो सकता है।

यह बीमारी एक-दूसरे के संपर्क में आने से होती है। इसके अलावा यदि आप इस बीमारी से संक्रमित किसी भी व्यक्ति के कपड़े, बिस्तर या फर्नीचर प्रयोग करते हैं तो यह आपको भी हो सकती है। भीड़भाड़ वाली जगहें, जैसे - जेल, नर्सिंग होम और बच्चों की देखभाल करने वाले स्थानों पर स्कैबीज संक्रमण के फैलने का खतरा अधिक होता है।

क्या होता है स्कैबीज

स्कैबीज त्वचा का वह संक्रमण है जो घुन के कारण होता है। जब घुन आपकी त्वचा की परत को भेदते हुए अंदर प्रवेश कर जाती है, तब यह समस्या होती है। स्कैबीज किसी को भी हो सकती है। यह किसी भी उम्र, आय और सामाजिक स्तर के लोगों को हो सकती है। यहां तक कि जो लोग स्वयं को बेहद स्वच्छ रखते है उन्हें भी स्कैबीज हो सकती है।

कैसे फैलती है

स्कैबीज घुन के काटने से तो फैलती ही है साथ ही यह बीमारी संक्रमित व्यक्ति के साथ शारीरिक नजदीकी से भी हो सकती है। यह एक संचारित रोग है, जो तौलिए, चादर और अन्य निजी वस्तुएं इस्तेमाल करने से हो सकती है। स्कैबीज एक साथ परिवार के कई सदस्यों को हो सकती है। इतना ही नहीं यदि किसी संक्रमित व्यक्ति को इसके लक्षण न भी नजर आ रहे हों, तब भी वह दूसरे व्यक्ति को इस रोग से संक्रमित कर सकता है।

लक्षण

स्कैबीज से गंभीर खुजली होती है, जो अक्सर रात के समय बढ़ जाती है। इसके साथ ही रेशेज के साथ छोटे फफोले और घाव हो जाते हैं। छोटे बच्चों और बुजुर्गों में खुजली की समस्या अधिक होती है। बच्चों की त्वचा अपेक्षाकृत अधिक संक्रमित होती है।

कैसे होता है निदान

डॉक्टर स्कैबीज के निदान की प्रक्रिया आपके लक्षणों के आधार पर करता है। स्कैबीज का सबसे कारण किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ शारीरिक संपर्क होता है। इसके बाद डॉक्टर बड़े आराम से संक्रमित और रूखी त्वचा को खुरचकर सूक्ष्मदर्शी द्वारा उसकी जांच करता है। अधिकतर लोगों को इस जांच से कोई दर्द नहीं होता।

कैसे होता है इलाज

स्कैबीज अपने आप ठीक नहीं होती। आपको डॉक्टर की सुझायी खास क्रीम अथवा लोशन का इस्तेमाल करना होता है। कुछ गंभीर मामलों में आपको दवा का भी सेवन करना पड़ सकता है। स्कैबीज में दी जाने वाली कुछ दवायें बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करवा रहीं माताओं के लिए सुरक्षित नहीं होतीं। इन दवाओं के खतरनाक प्रभावों से बचने के लिए अपने डॉक्टर की सुझाई दवाओं को सही प्रकार पालन करें और डॉक्टरी सलाह को अनदेखा न करें। अगर आपको स्कैबीज है, तो आपको और आपके समीप रहने वाले परिजनों का इलाज एक ही समय पर होना चाहिए। इससे संक्रमण फैलने का खतरा कम हो जाता है। इसके साथ ही आपको अपने कपड़े और तौलिए आदि भी सावधानीपूर्वक साफ करने चाहिए। घावों से होने वाले रक्तस्राव भी अच्छी तरह साफ करना चाहिए। इलाज के बाद सामान्य दो से चार सप्ताह तक खुजली रहती है। घुन के द्वारा हुई एलर्जी को दूर करने में आपके शरीर को इतना समय तो लगता ही है।

बैटरी बर्बाद कर रहे ये एप्स...

एक स्मार्टफोन कितना भी स्मार्ट हो, एप्स के बगैर अधूरा ही रहता है। स्मार्टफोन को खरीद कर हम सबसे पहला काम एप्स डाउनलोड करने का ही करते हैं। इनमें कई तरह के एप्स शामिल होते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट के, तो कुछ जरूरी काम के। साथ ही कुछ ऐसे भी होते हैं, जो कभी-कभार काम आते हैं, लेकिन, क्या आप जानते हैं कि इन एप्स का आपके फोन पर क्या असर पड़ता है?

स्मार्टफोन में मौजूद कई एप्स वाकई जरूरी होते हैं, और वह आपके फोन के लिए भी सुरक्षित होते हैं लेकिन, ऐसे भी कई एप्स होते हैं, जो आपके फोन की बैटरी लाइफ को बरबाद कर देते हैं। ये एप्स हर समय आपके स्मार्टफोन में रन करते हैं, चाहे आप फोन इस्तेमाल कर रहे हों या नहीं। यही कारण है कि कई स्मार्टफोन यूजर्स को बैटरी लाइफ से शिकायत होती है। फोन को कितना भी चार्ज किया जाए, उसकी बैटरी बहुत जल्दी खत्म होने लगती है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ एप्स के नाम बताने वाले हैं, जिन्हें आप न ही डाउनलोड करें, तो अच्छा होगा। इनमें से कई एप्स बेहद फेमस भी हैं।

गेमिंग एप

कई गेमिंग ऐप्स भी हैं, जो आपके फोन की बैटरी लाइफ को खतरे में डालते हैं। जैसे कि हाल ही में खासा लोकप्रिय रहा पोकेमोन गो जैसे गेम भी काफी हद तक फोन की बैटरी लाइफ को कम करते हैं।

फेसबुक एप: यह एप लगभग हर स्मार्टफोन यूजर के फोन में होता है। हम में से कई इस पर पूरा टाइम एक्टिव भी रहते होंगे। लेकिन, आपको जान कर हैरानी होगी कि फेसबुक एप सबसे ज्यादा बैटरी इस्तेमाल करनेवाले ऐप्स में से एक है।

स्नैपचैट: सोशल मीडिया एप्स सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। इन दिनों स्नैपचैट का बुखार सभी को है, चाहे वह कोई सेलेब्रिटी हो या आम यूजर। यह एप्प भी मोबाइल स्टोरेज के साथ ही बैटरी भी अधिक खर्च करता है।

नेटफ्लिक्स: इसमें कोई शक नहीं कि नेटफ्लिक्स भी उन एप्स में से एक है, जो अधिक बैटरी कंज्यूम करता है। इस एप्प से फोन की बैटरी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है।

एवीजी एंटी वायरस एप्प

एंटी वायरस एप्प आपके फोन की सुरक्षा के लिए काम आते है, लेकिन आपको बता दें कि ये फोन की बैटरी की सुरक्षा नहीं करते है, बल्कि काफी बैटरी खर्च करते है।

AVG

सफल फेंगशुई का आधार...

फेंगशुई ऊर्जा को संतुलित करने की पद्धति का नाम है। इनके संतुलन से ही फेंगशुई प्रभावकारी होता है। इस विधा में जल, लकड़ी, अग्नि, पृथ्वी और धातु की दिशा के अनुरूप व्यवस्था ही सफल फेंगशुई का निर्माण करती है। यही कारण है कि घर का निर्माण ऐसा होना चाहिए कि सूरज की रोशनी घर में अवश्य आए। चीनी वास्तु फेंगशुई का इतिहास करीब तीन हजार वर्ष पुराना है। फेंगशुई का शाब्दिक अर्थ है हवा और पानी। यह विधा पांच तत्वों पर आधारित है- जल, लकड़ी, अग्नि, पृथ्वी और धातु। इस विधा में नाकारात्मक ऊर्जा यिन व साकारात्मक ऊर्जा यांग के नाम से जानी जाती है। ये परस्पर विरोधी ऊर्जाएं हैं, जो एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करती हैं। इसके अतिरिक्त ब्राह्मांड की ऊर्जा जिसे ची के नाम से जाना जाता है। फेंगशुई, ब्राह्मंड की ऊर्जा तथा यिन व यांग। घर की ऊर्जा व दिशाओं के अनुरूप तत्वों को व्यवस्थित करना और घर में रसोई, मुख्य शयन कक्ष, बच्चों का शयनकक्ष, धन व बहुमूल्य वस्तुओं को रखने का कक्ष या अलमारी, पढ़ाई का कक्ष आदि की तत्वों व दिशाओं के अनुरूप व्यवस्था ही सफल फेंगशुई का आधार है। जो घड़ियां बंद हों, उन्हें या तो घर से हटा देना चाहिए या फिर चालू कर देना चाहिए। घर में झाड़ू का उपयोग करने के बाद उसे इस तरह रखना चाहिए कि किसी की इस पर नजर न जाए। फेंगशुई के अनुसार इसका संबंध घर के धन और संपत्ति से होता है। पूरे घर में कालीन बिछा देने से पॉजिटिव शक्तियां घर के अंदर नहीं रह पाती। शीशे को घर के मुख्य द्वार पर नहीं लगाना चाहिए। बाथरूम के दरवाजे के ठीक सामने भी कोई शीशा नहीं होना चाहिए। घर में बच्चों को डर लगे तो पीले रंग का बल्ब लगाना चाहिए। घर का मुख्य द्वार अन्य दरवाजों की तुलना में बड़ा होना चाहिए। मुख्य गेट दो पल्लों का होना चाहिए। मुख्य द्वार के दोनों ओर खिड़कियां नहीं होने चाहिए, इससे घर के मालिक को आर्थिक परेशानी हो सकती है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव दूर करने के लिए चीनी बेम्बू का प्रयोग करें। भाग्य को चमकाने के लिए मकान या व्यापार स्थल के मुख्य द्वार पर पवन घंटियां तथा चीनी सिक्के लगाएं। कछुए को घर में रखना प्रगति व स्वास्थ्य की दृष्टि से शुभ होता है।

कलिंग समाचार

सोमवार 10 अगस्त 2026

करप्शन अगेंस्ट इंडिया

2004 से लेकर 2014 तक देश में यूपीए शासन रहा, जिसकी अगुवाई कांग्रेस ने की। इस सरकार पर 2010 में हुए कॉमनवेल्थ गे स, कोयला ब्लॉक आबंटन और 2जी स्पेक्ट्रम के आबंटन में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। 2011 में अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार मिटाने के लिए लोकपाल लाने के नाम पर ही लंबा आंदोलन किया। जिसमें भाजपा और मीडिया का पूरा साथ रहा। तब फिल्म जगत के लोगों ने भी डॉ.मनमोहन सिंह का खूब मजाक उड़ाया। तब केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई पर भी सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख़ टिप्पणी करते हुए उसे पिंजरे का तोता कहा था। कांग्रेस के खिलाफ बने इस माहौल का ही असर था कि 2014 में भाजपा की सरकार बनी और इसके बाद कभी कांग्रेसमुक्त भारत तो कभी विपक्षमुक्त भारत बनाने की कोशिशें हुईं। यह और बात है कि भाजपा की ये कोशिशें नाकाम रहीं, मगर देश के लोकतांत्रिक ढांचे को इसमें जबरदस्त नुकसान हुआ है। ये सारी बातें इस समय करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कोयला ब्लॉक आबंटन मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ़ आपराधिक मामले को बंद कर दिया और उन्हें समन जारी करने के आदेश को रद्द कर दिया है। इसके बावजूद विशेष अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी थी और 2015 में उन्हें आरोपी के रूप में तलब कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा कि विशेष अदालत के पास सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को ठुकराने का कोई ठोस कारण नहीं था, इसलिए अदालत ने उस आदेश को रद्द करते हुए मामला गुण-दोष के आधार पर बंद कर दिया। चूंकि 27 दिसंबर 2024 में मनमोहन सिंह का निधन हो चुका था, इसलिए यह फैसला उन्हें मरणोपरांत कानूनी राहत देने वाला माना जा रहा है। डा. सिंह अपने निर्दोष होने के फैसले को सुनने के लिए इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन जनवरी 2014 में अपनी आखिरी प्रेस कांफ्रेंस में मनमोहन सिंह ने भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े सवाल पर कहा था, मैं इस मामले में थोड़ा दुखी महसूस करता हूं क्योंकि मैंने ही इस बात पर ज़ोर दिया था कि स्पेक्ट्रम आबंटन पारदर्शी और निष्पक्ष हो। मैं ही था जिसने ज़ोर देकर कहा था कि कोल ब्लॉक का आबंटन नीलामी के आधार पर हो, लेकिन इन तथ्यों को भुला दिया गया। इस मामले में विपक्ष का अपना स्वार्थ निहित था। कुछ मौक़ों पर मीडिया उनके हाथ का खिलौना भी बन गया। उन्होंने कहा था कि %इसलिए मेरे पास इसकी हर वजह है कि जब भी इस समय का इतिहास लिखा जाएगा, हम बेदाग़ बाहर आएंगे। मनमोहन सिंह ने कहा, मैं मानता हूं कि इतिहास मेरे प्रति आज के मीडिया के मुक़ाबले ज़्यादा उदार होगा। मनमोहन सिंह ने कहा कि %यह फ़ैसला इतिहासकारों को करना है कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। महज 12 साल पहले का ऐसा राजनैतिक माहौल अब सपने जैसा नजर आता है कि प्रधानमंत्री प्रेस कांफ्रेंस किया करते थे, अपने ऊपर और अपनी सरकार पर लगे आरोपों को लेकर जवाब देते थे। अब न तो प्रधानमंत्री प्रेस कांफ्रेंस करते हैं, न मीडिया के लोग उनसे भ्रष्टाचार पर बातें करते हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी तो ताजा प्रकरण है, पिछले बारह बरसों में कई और ऐसे प्रकरण हुए, लेकिन हर बार नैरेटिव बदल कर सरकार को जवाबदेही से निकलने का मौका मीडिया देता रहा। फिलहाल नरेन्द्र मोदी तो यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि इतिहास मेरे साथ न्याय करेगा। लेकिन डॉ.मनमोहन सिंह जानते थे कि सच कभी पराजित नहीं होता, इसलिए उन्होंने पहले ही अपने साथ होने वाले न्याय की बात कह दी थी। दरअसल कोयला ब्लॉक आबंटन में यह आरोप लगाए गए कि सरकार ने निजी कंपनियों को बिना बोली लगाए आबंटन कर दिया, इससे कम से कम 10 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। यूपीए सरकार में कोयला सचिव रहे पी.सी. पारेख, इस मामले में व्हिसलब्लोअर माने जाते हैं। पारेख ने दावा किया था कि उन्होंने 2004 में ही प्रधानमंत्री को विवेकाधीन आबंटन प्रक्रिया में धोखाधड़ी की संभावना के बारे में लिखित रूप में सूचित किया था और खुली नीलामी की वकालत की थी। आरोप था कि प्रधानमंत्री ने इसे नजरअंदाज कर दिया और उनके कोयला मंत्रालय के कार्यकाल में बिना नीलामी के 142 कोयला ब्लॉक आबंटित कर दिए गए।

लंबे समय से पाठ्य पुस्तकों के ज़रिए खराब किया जा रहा है बच्चों का दिमाग

डॉ. ज्ञान पाठक

पुस्तकें व साहित्य मौजूदा मामले में, सर्वोच्च न्यायालय की मु य चिंताएं न्यायपालिका के चित्रण, संस्थागत विश्वसनीयता को संभावित रूप से कमज़ोर करने और स्कूली छात्रों के लिए पाठ्य सामग्री तैयार करने के तरीके के इर्द-गिर्द घूमती रहीं। लेकिन, गहरी और सोची-समझी साज़िश एक पुराना आरोप है जो 2014 से कई दूसरे मामलों से जुड़ी कई पाठ्यपुस्तकों में बदलाव के लिए लगाया जाता रहा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी)की एक किताब पर पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है, और एक पाठ के खास संदर्भ में गहरी जड़ें और सुनियोजित साज़िश% शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसमें न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार और उसके कामकाज पर चर्चा की गई है। केवल एक निष्पक्ष जांच ही साज़िश के सभी आयामों को सामने ला सकती है, जो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से पूरे देश के सामाजिक और राजनीतिक ताने-बाने के लिए खतरा बनी हुई है। सवाल यह है कि क्या इस साजिश में आरएसएस-भाजपा कुनबे की सरकार शामिल है और साज़िश की जड़ें कहीं उससे भी ज्यादा गहरी हैं जितनी कि अभी टिप्पणी की गयी है? मौजूदा मामले में, सर्वोच्च न्यायालय की मु य चिंताएं न्यायपालिका के चित्रण, संस्थागत विश्वसनीयता को संभावित रूप से कमज़ोर करने और स्कूली छात्रों के लिए पाठ्य सामग्री तैयार करने के तरीके के इर्द-गिर्द घूमती रहीं। लेकिन, गहरी और सोची-समझी साज़िश एक पुराना आरोप है जो 2014 से कई दूसरे मामलों से जुड़ी कई पाठ्यपुस्तकों में बदलाव के लिए लगाया जाता रहा है। भारत को यह जानने की ज़रूरत है कि आरएसएस-भाजपा की सरकार पाठ्यपुस्तक में बदलाव के ज़रिए हमारे बच्चों को एक खास तरीके से गुमराह करने के लिए पूरी शिक्षा प्रणाली को बदलने में किस हद तक शामिल रही है। मौजूदा मामले में, भारत के मु य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने एनसीईआरटी और केंद्र और राज्य शिक्षा विभागों को यह पक्का करने का आदेश दिया है कि किताब की सभी कॉपी, चाहे वह हार्ड कॉपी हो या डिजिटल, जनता की पहुंच से हटा दी जाएं। सीजेआई ने कहा, %हम और गहरी जांच चाहते हैं। हमें यह पता लगाना होगा कि कौन ज़िम्मेदार है और हम देखेंगे कि कौन लोग हैं। सज़ा मिलनी चाहिए! विवादित बातें सामने आने के बाद एनसीईआरटी निदेशक द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को दी गई जानकारी पर पीठ ने कड़ी आपत्ति जताई। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, %किताब में जो कुछ भी बहुत ही बेइज्जती और लापरवाही से लिखा गया है, उस पर अपनी राय देने के बजाय, एससीईआरटी के निदेशक ने जवाब में लिखित सामग्री का बचाव किया।% ज़्यादा जानें संपादकीय लेखन कार्यशाला ताज़ा ख़बरें सूचना भारतीय इतिहास पुस्तकें न्यायालय के आदेश में कहा गया, %हमें ऐसा लगता है कि यह संस्थागत अधिकार को कमज़ोर करने और न्यायपालिका की इज्ज़त को गिराने की एक सोची-समझी चाल है। अगर इसे ऐसे ही चलने दिया गया, तो यह आम लोगों और युवाओं के आसानी से प्रभावित होने वाले मन में न्यायिक कार्यालय की पवित्रता को खत्म कर देगा।

ये तो न्यायपालिका से जुड़े सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। कई और भी मामले हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर भारत को उस %गहरी और सोची-समझी साज़िश% का पर्दाफ़ाश करने की ज़रूरत है, जिसकी ओर सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने इंगित किया है। भारत में एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों को कैसे बदला जाता है, इस पर विवाद और राजनीतिक बहसें होती रही हैं — विपक्ष और नागरिक समाज के आलोचकों का दावा है कि ये बदलाव सरकार और उसके सैद्धान्तिक समर्थक भाजपा और आरएसएस की इतिहास और सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई को नया रूप देने की कोशिश को दिखाते हैं। आलोचकों— जिनमें नेता और अकादमिक भी शामिल हैं — का आरोप है कि एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में हाल के बदलाव राजनीति से प्रेरित संपादन या इतिहास का भगवाकरण दिखाते हैं।

केरल के मु यमंत्री पिनाराई विजयन ने एनसीईआरटी पर महात्मा गांधी की हत्या, आरएसएस पर प्रतिबंध और मुगल इतिहास के कुछ हिस्सों जैसी घटनाओं से जुड़े पाठ और भाग हटाने का आरोप लगाया है, और कहा है कि इनका मकसद इतिहास के बारे में आरएसएस से जुड़े नज़रिए को बढ़ावा देना है। राजनीतिक बहस मंच मणिकम टैगोर जैसे विपक्षी नेताओं ने कहा है कि भाजपा स्कूल की किताबों में आरएसएस के आ यान को आगे बढ़ा रही है। अकादमिक योगेंद्र यादव और सुहास पलशिकर ने एनसीईआरटी द्वारा बिना उनकी मंज़ूरी के उनके नाम से बदली हुई पाठ्यपुस्तक प्रकाशित करने पर सबके सामने एतराज़ जताया। पाठ्यपुस्तकों को तर्कसंगत करने के पहले के दौर (जैसे, क्लास 9 और 12 में चैप्टर हटाना) की आलोचना की गई थी, जिसमें मु य ऐतिहासिक घटनाओं को नज़रअंदाज़ करने या इस्लामिक इतिहास के कवरेज को कम करने की बातें कही गयी थीं। मु य आरोपों में से एक यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार फासीवाद का पालन करने के रास्ते पर चल रही है और देश पर सर्वोच्च नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है, जिसमें न्यायपालिका को नियंत्रित करना भी शामिल है। इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय की %गहरी जड़ें और सुनियोजित साज़िश' की टिप्पणी का महत्व और भी बढ़ जाता है। इतिहास के भगवाकरण का एक मु य आरोप रहा है। यह आरोप लगाया गया है कि पाठ्यपुस्तक को भाजपा और आरएसएस से जुड़े हिंदू राष्ट्रवादी नज़रिए को दिखाने के लिए बदला जा रहा है। आलोचकों का तर्क है कि प्राचीन भारत को ज़्यादा स यता-गौरवशाली शब्दों में पेश किया गया है, वैदिक ज्ञान और स्वदेशी वैज्ञानिक उपलब्धियों पर ज़ोर दिया गया है, इस्लामिक और मुगलकाल को तुलना में कम या फिर से बनाया गया है, और धर्मनिरपेक्ष इतिहास लेखन पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे रखा गया है। पाठ्यक्रमों को तर्कसंगत बनाने के (2020-2023) के दौर में, आलोचकों ने इन बातों पर ध्यान दिया था- मुगलों पर विस्तार से बताये गये पाठों को हटाना या छोटा करना; दरबारी संस्कृति के संदर्भों में कमी, प्रशासन, और मिली-जुली परंपराएं; और दिल्ली सल्तनत के शासकों पर पाठ्य सामग्री को कम करना। इतिहासकारों का तर्क है कि इससे समानुपातिक ऐतिहासिक कवरेज बिगड़ती है। एनसीईआरटी का कहना है कि कटौती महामारी के समय में पाठ्यक्रम का बोझ कम करने का हिस्सा थी। शैक्षिक संसाधन महात्मा गांधी की हत्या और आरएसएस पर प्रतिबंध से जुड़े बदलावों में महत्वपूर्ण था महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर लगे प्रतिबंध के ज़िक्र को कम करना या बदलना। इसने हत्या के आस-पास की चर्चाओं को भी नए सिरे से तैयार किया। आलोचकों का दावा है कि इससे आज़ादी के बाद के भारत में चरमपंथी राजनीति पर चर्चा कमज़ोर होती है। एनसीईआरटी का कहना है कि ज़रूरी तथ्य वैसे ही हैं और संपादन तकनीकी या पढ़ाने की प्रक्रिया से जुड़े थे। आज की राजनीतिक घटनाओं से जुड़ी पाठ्य सामग्री भी हटा दी गयी। हटाए गए या काटे गए पाठों में शामिल हैं 2002 के गुजरात दंगों पर चर्चा; विरोध और सामाजिक आंदोलनों पर पाठ्य सामग्री; बढ़ती असहिष्णुता पर बहस के ज़िक्र; और कुछ वर्ग में लोकतंत्र और असहमति पर किताबों के कुछ भाग। शिक्षा कुछ समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान की पाठ्य सामग्री कथित तौर पर कम की गयी है जिनमें शामिल हैं जाति-आधारित असमानताओं पर चर्चा; अल्पसं यक संघर्षों पर किताबों के कुछ भाग; और भेदभाव और सांप्रदायिक संघर्ष का ज़िक्र करने वाले हिस्से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)2020 के बाद के दौर में, नए पाठ्यक्रमों में स यता से जुड़ी कहानी की ओर बदलाव हो रहा है। भाषा की बनावट और लहजे में बदलाव हैं। ऐसे और भी कई आरोप लगे हैं जो बताते हैं कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से आगे भी %गहरी और सोची-समझी साज़िश' फैली हुई है। इसलिए, पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और साज़िश का पर्दाफ़ाश होना चाहिए।

दक्षिण एशिया सुरक्षा पर वाशिंगटन का आक्रामक रवैया

नित्य चक्रवर्ती

बीजिंग बांग्लादेश में हो रहे विकासक्रम पर करीब से नज़र रख रहा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद डॉ. यूनुस से उनकी बैठक में मिले और बांग्लादेश के साथ रिश्ते बढ़ाने में व्यक्तिगत दिलचस्पी दिखाई ताकि यह दक्षिण एशियाई देश चीनी मदद से अच्छी-खासी नौकरियां पैदा कर सके। चीन नहीं चाहेगा कि अमेरिका के दबाव की वजह से उसके समझौते रद्द हो जाएं। 12 फरवरी के राष्ट्रीय चुनाव में अपनी पार्टी की शानदार जीत के बाद बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान को बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बने हुए सिर्फ़ एक ह ता हुआ है। 60 साल के प्रधानमंत्री, जो ब्रिटेन में 17 साल के देश निकाला के बाद स्वदेश लौटे हैं, से उ मीद की जा रही थी कि वे देश की खराब अर्थव्यवस्था और इसके प्रशासन को फिर से दुरुस्त करने को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देंगे, लेकिन उनके ध्यान का केन्द्र अचानक बदल गया है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका प्रशासन बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गया है और नई सरकार से चीन के खिलाफ़ रूख अपनाने के लिए कहकर बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है।

अमेरिका की तरफ़ से ऐसा खुला दावा हाल के महीनों में नहीं देखा गया है। असल में, अंतरिम सरकार के पहले के आधे समय में अमेरिकी दूतावास के अधिकारी इतने सक्रिय नहीं थे, लेकिन 12 फरवरी के चुनाव पास आते ही हालात बदल गए। बांग्लादेश को लेकर ट्रंप प्रशासन के नज़रिए में अचानक बदलाव आया। नए अमेरिकी राजदूत ब्रेंटक्रिस्टेंसन ने इस साल 12 जनवरी को ढाका में अपना कार्यभार संभाला, अर्थात 12 फरवरी के चुनाव से ठीक एक महीना पहले। तब से ब्रेंट समेत अमेरिकी अधिकारी बीएनपी और जमात दोनों नेताओं को साध रहे हैं ताकि चीनी राजदूत योवेन को मात दी जा सके, जो पिछले तीन सालों से ढाका में सक्रिय हैं और सरकार और राजनीतिक पार्टियों के हर स्तर पर बड़े स पर्क बना रहे हैं। राजनीतिक बहस मंच,द्यह्रश्व ऱ्द्धड्डह्य - आखिर ईरान पर हमलों की वजह क्या है? प्रधानमंत्री तारिक रहमान और उनके विदेश मंत्री खलीलुर रहमान के पद संभालने के बाद, जो एक बहुत अनुभवी विदेश सेवा अधिकारी थे, ने हमेशा की तरह तीन बड़े देशों भारत, अमेरिका और चीन के साथ रिश्तों की पुनर्समीक्षा की और बांग्लादेश के फायदे के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इस पर बात की। अभी-अभी घोषित अमेरिका-बांग्लादेश व्यापार समझौते की समीक्षा पर भी चर्चा हुई। तीनों बड़े देशों के साथ रिश्तों में संतुलन बनाने के मुद्दे दृष्टिपटल पर थे।

जब शनिवार 21 फरवरी को शुरुआती बातचीत चल रही थी, तो अमेरिकी राजदूत ब्रेंटक्रिस्टेंसन ने बिना बांग्लादेश का नाम लिए, एक कड़े बयान में कहा कि, वह दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते असर को लेकर परेशान हैं। ट्रंप की तरफ से तारिक को भेजे गए पत्र में यह भी कहा गया था कि अमेरिका-बांग्लादेश साझेदारी आपसी स मान और एक मुक्त और खुला भारत-प्रशांत को बढ़ावा देने में एक जैसे फायदे पर आधारित है। इसका असल में मतलब है कि अमेरिका अब चीन के खिलाफ अपनी भारत-प्रशांत सुरक्षा रणनीति में बांग्लादेश को एक भागीदार के तौर पर चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे ट्रंप ने अपनी चीन विरोधी सुरक्षा रणनीति में भारत को एक भागीदार के तौर पर शामिल किया है। ज़्यादा जानें समाचार सदस्यता शीर्षक खोज उपकरण चुनावी जागरूकता अभियान,द्यह्रश्व ऱ्द्धड्डह्य - राजस्थान की अनोखी तालाब संस्कृति इस प्रकार तारिक रहमान के लिए, अपनी स्थिति को स्थिर किये जाने से पहले ही, उन्हें अमेरिका की तरफ से यह धमकी मिल रही है कि अगर नई सरकार अमेरिका के साथ बेहतर रिश्ते बनाना चाहती है, तो उसे चीन के खिलाफ अमेरिका की रणनीति का हिस्सा बनना होगा। ज़ाहिर है, अगले दिन चीन ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी, जब चीनी दूत योवेन ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री से मुलाकात की और कहा कि चीन बांग्लादेश की %सर्वप्रथम बांग्लादेश नीति' को मानने की घोषणा की तारीफ़ करता है और ढाका को चीन का सहयोग हर जगह होगा और यह किसी तीसरे देश के खिलाफ़ नहीं है। तारिक सरकार ढाका की धरती से अमेरिकी दूतावास के चीन विरोधी रवैये से बहुत शर्मिंदा है, लेकिन सरकार अमेरिका को बड़े भाई की भूमिका निभाने से रोकने के लिए बहुत कम काम ही कर सकती है। ढाका में राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि बांग्लादेश और चीन के बीच पिछले रक्षा समझौते से अमेरिका चिंतित है। अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश रक्षा सहयोग के लिए चीन के साथ अपनी भविष्य की बातचीत को आगे न बढ़ाए। जहां तक धारणा का सवाल है, बांग्लादेश के लोग ज़्यादातर भारत और अमेरिका दोनों के खिलाफ़ भावनाएं रखते हैं। 5 अगस्त, 2024 को हसीना सरकार के गिरने के बाद से पिछले अठारह महीनों में, अमेरिका के लिए भावनाओं में गिरावट की तुलना में लोगों के बीच चीन का प्रभाव बढ़ा है। 2025 की शुरुआत में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख डॉ. यूनुस के चीन दौरे में, बांग्लादेश के अलग-अलग जिलों में औद्योगिक क्षेत्र बनाने में चीन के निवेश में एक बड़ी कामयाबी मिली। बांग्लादेश में भारतीय सीमा के पास ड्रोन के लिए एक फैक्टरी लगाने का समझौता हुआ। तारिक सरकार से अब अमेरिका ने उस समझौते की नए सिरे से समीक्षा करने को कहा है। स्थानीय उत्पाद प्रचार हाल ही में हस्ताक्षरित हुए अमेरिकी व्यापार समझौते की एकतरफ़ा शर्तों ने दिखाया है कि कैसे नए बांग्लादेशी प्रधानमंत्री तारिक रहमान को वॉशिंगटन और बीजिंग के साथ रिश्तों को लेकर एक नाजुक संतुलन बनाने के चुनौतीपूर्ण कार्य से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों उनके देश में असर डालने की होड़ में हैं। एक तरफ़, अमेरिका अपने बाजार तक पहुंच, सुरक्षा सहयोग और विनियामक लाभ का प्रचार कर रहा है, तो दूसरी ओर चीन अवसंरचना, औद्योगिक समेकीकरण और रक्षा उपकरणों की आपूर्ति का वादा कर रहा है। चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और एक बड़ा अवसंरचनात्मक निवेशक बना हुआ है, जो बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से लेकर औद्योगिक क्षेत्रों तक के परियोजनाओं को वित्तपोषित कर रहा है। अमेरिका बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है और लंबे समय से इसका सबसे बड़ा विदेशी निवेशक रहा है, हालांकि प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश (एफडीआई) स्टॉक तेज़ी से गिरा है। जून 2023 तक के वित्तीय वर्ष में लगभग 4 अरब डॉलर से गिरकर सितंबर 2025 तक यह लगभग 1 अरब डॉलर तक नीचे आ गया है, विशेषकर यूनुस राज के दौरान राजनीतिक उथल-पुथल और निवेशकों के कमज़ोर भरोसे की वजह से। राजनीतिक बहस मंच सितंबर 2025 तक बांग्लादेश में चीनी एफडीआई स्टॉक लगभग 3 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। बीजिंग ने कई दूसरे कम विकसित देशों के साथ-साथ बांग्लादेशी निर्यात को शून्य-टैरिफ पहुंच भी दिया है। पहले 2022 में 98 प्रतिशत उत्पादनों को सीमाशुल्क-मुक्त पहुंच दिया और बाद में इस पेशकश को बढ़ाया। चीन बांग्लादेश को एक बड़ा रक्षा प्रणाली आपूर्तिकर्ता के तौर पर अपनी जगह बनाए रखने के लिए बहुत उत्सुक है। अब ट्रंप प्रशासन इस पर एतराज़ कर रहा है। पहले के सालों में ऐसी स्थिति नहीं थी। ज़्यादा जानें हिंदी समाचार सदस्यता प्रादेशिक समाचार संग्रह दैनिक समाचार अपडेट बीजिंग बांग्लादेश में हो रहे विकासक्रम पर करीब से नज़र रख रहा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद डॉ. यूनुस से उनकी बैठक में मिले और बांग्लादेश के साथ रिश्ते बढ़ाने में व्यक्तिगत दिलचस्पी दिखाई ताकि यह दक्षिण एशियाई देश चीनी मदद से अच्छी-खासी नौकरियां पैदा कर सके। चीन नहीं चाहेगा कि अमेरिका के दबाव की वजह से उसके समझौते रद्द हो जाएं। तारिक रहमान पर उनके सलाहकारों और थिंक टैंक की तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव है कि वे बांग्लादेश प्रथम नीति पर टिके रहें और बीएनपी चुनावी घोषणापत्र के मुताबिक बांग्लादेश की रणनीतिगत स्वायत्तता को ध्यान में रखकर काम करें। अगले कुछ दिन बताएंगे कि क्या तारिक में अमेरिका के दबाव को नज़रअंदाज़ करने और सिर्फ बांग्लादेश के हितों को ध्यान में रखकर काम करने की हिम्मत है?

विविध समाचार

आज दुनिया भारत की ओर उम्मीद लगाए देख रही : अनुराग ठाकुर

शिमला। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने शिमला के जाखू हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस दौरान पीएम मोदी के नेतृत्व पर बात की और राज्य में स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज दुनिया भारत की ओर उम्मीद लगाए देख रही है। अनुराग ठाकुर ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "ऐसा नहीं है कि जब आप भगवान के चरणों में आते हैं, तो सिर्फ कुछ मांगने ही आते हैं। जाखू हनुमान मंदिर एक बहुत पुरानी जगह है। अगर आप इसके आस–पास के खूबसूरत नजारों को देखें, तो आपके अंदर अपने आप ही सकारात्मक ऊर्जा का एहसास जाग उठता है। मेरा मानना है कि जो कोई भी शिमला आता है और जाखू मंदिर नहीं जाता, उसकी यात्रा एक तरह से अधूरी रह जाती है।"

3 महीने तक फ्री में बनेंगे सभी सर्टिफिकेट, अवैध ा कॉलोनियों को लेकर भी हुआ अहम ऐलान

चंडीगढ़। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य की जनता को बड़ी राहत देते हुए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। बुधवार को हुई अहम कैबिनेट बैठक के बाद, कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन जनहितैषी फैसलों की विस्तार से जानकारी दी।

सरकार ने आम नागरिकों की जेब का बोझ कम करने के साथ–साथ किसानों और घर खरीदारों के लिए भी कई महत्वपूर्ण रियायतों का ऐलान किया है, जिससे प्रदेश के लाखों लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा। इस समय चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट के संशोधन का काम चल रहा है, जिसके कारण लोगों को कई तरह के दस्तावेजों की जरूरत पड़ रही है। इसे देखते हुए पंजाब सरकार ने गरीब और ग्रामीण तबके को बड़ी आर्थिक राहत दी है। मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि 1 जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026 तक रिहायशी, जाति, जन्म और शैक्षणिक योग्यता के सर्टिफिकेट बनवाने पर लगने वाली सुविधा फीस पूरी तरह से माफ कर दी गई है। पहले डोर–स्टेप डिलीवरी सेवाओं के लिए 70 रुपये और अन्य के लिए 50 रुपये फीस लगती थी, जो अब इन तीन महीनों के लिए एकदम फ्री होगी। राज्य में विकास कार्यों के लिए अधिग्रहित की जाने वाली जमीन के मालिकों और किसानों को भी सरकार ने बड़ी राहत दी है। पुरानी नीति में बदलाव करते हुए, अब प्रति एकड़ जमीन के बदले मिलने वाले 200 गज के कमर्शियल प्लॉट का आकार बढ़ाकर 210 गज कर दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति कमर्शियल प्लॉट नहीं लेना चाहता, तो उसे रिहायशी प्लॉट में 30 गज का अतिरिक्त फायदा देकर कुल 1630 गज का प्लॉट दिया जाएगा। कमर्शियल प्रोजेक्ट वाली जगहों पर भी 800 गज की सीमा को बढ़ाकर 840 गज कर दिया गया है। इसके अलावा, जिन लोगों की 1 एकड़ या उससे ज्यादा जमीन अधिग्रहित होगी, उन्हें बिना किसी नीलामी के सरकारी रिजर्व प्राइस पर एक अतिरिक्त प्लॉट लेने का विकल्प भी मिलेगा। पंजाब भर में बिना मंजूरी के बनी अवैध कॉलोनियों के मुद्दे पर भी कैबिनेट ने एक बड़ा और स्पष्ट फैसला लिया है। नई नीति के तहत, जिन अवैध कॉलोनियों में कम से कम 25 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, उन्हें अब सरकार द्वारा नियमित (रेगुलर) किया जाएगा। इसके लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या डेवलपर को रिहायशी इलाके के लिए कलेक्टर रेट (डीसी रेट) का 5 फीसदी और कमर्शियल इलाके के लिए 10 फीसदी चार्ज जमा करवाना होगा। प्रक्रिया पूरी होने पर सरकार पहले प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी करेगी और साढ़े चार साल में कॉलोनी विकसित होने के बाद ही आगे प्लॉटों की खरीद–फरोख्त हो सकेगी। सरकार के इस फैसले का सबसे बड़ा और सीधा फायदा उन आम लोगों को मिलेगा, जिन्होंने इन कॉलोनियों में अपनी गाढ़ी कमाई लगाई है। जो कॉलोनियां इस नई सरकारी प्रक्रिया के तहत नियमित हो जाएंगी, वहां के निवासियों या नए प्लॉट खरीदारों को अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री (सेल डीड) करवाने के लिए संबंधित अथॉरिटी से किसी भी प्रकार की NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

हालांकि, चीमा ने स्पष्ट किया कि यह छूट केवल उन्हीं कॉलोनियों को मिलेगी, जिनके मुख्य मालिक या डेवलपर ने सरकार की इस नई नीति और प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया होगा।

संत कबीर मानवता के मार्गदर्शक और सामाजिक जागृति के अगुआ–नायब सैनी

चंडीगढ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि संत कबीर मानवता के महानतम मार्गदर्शकों, सामाजिक चेतना के अग्रदूत और असाधारण संत थे। उनकी शिक्षाएं आज भी समाज को समानता, भाईचारे और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। उन्होंने लोगों से संत कबीर के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री अपने आधिकारिक आवास 'संत कबीर कुटीर' में आयोजित संत कबीर जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने घोषणा की कि अगले वर्ष संत कबीर जयंती का राज्य स्तरीय समारोह भिवानी में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर पद्मश्री प्रहलाद सिंह तिपानिया ने कबीर वाणी की प्रस्तुति दी। सैनी ने कहा कि संत कबीर ने अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव और सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हुए समानता, मानवता और सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की सभी योजनाएं "हरियाणा एक, हरियाणवी एक" की भावना से प्रेरित हैं और संत–महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के माध्यम से संतों के विचारों का प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि महान संत के सम्मान में उनके आधिकारिक आवास का नाम 'संत कबीर कुटीर' रखा गया है, जो जनसेवा, पारदर्शिता और लोककल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने कहा कि आधुनिक दौर में युवाओं को संत कबीर की शिक्षाओं से जोड़ना समय की आवश्यकता है।

पंजाब कांग्रेस ने चुनावी तैयारियां की तेज, राजा वड़िंग प्रदेश अध्यक्ष बरकरार, चरणजीत चन्नी को बड़ी जिम्मेदारी

चंडीगढ़। आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस हाईकमान ने राज्य में संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए चुनावी समितियों का गठन कर दिया है।

पार्टी ने अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए रखा है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष की मंजूरी के बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने नई नियुक्तियों की आधिकारिक सूची जारी की। वहीं, प्रताप सिंह बाजवा को कांग्रेस विधायक दल का नेता बरकरार रखा गया है। पार्टी ने विजय इंदर सिंगला को इलेक्शन मैनेजमेंट एंड को–ऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरपर्सन बनाया है। वहीं, सुखजिंदर सिंह रंधावा को कोर कमेटी और डॉ. अमर सिंह को मेनिफेस्टो कमेटी की कमान सौंपी गई है। कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सुखविंदर सिंह डैनी, राज कुमार वेरका और संगत सिंह गिलजियां को कार्यकारी अध्यक्ष (वर्किंग प्रेसिडेंट) नियुक्त किया है। माना जा रहा है कि इन नियुक्तियों से पार्टी विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी। कैंपेन कमेटी में सुखपाल सिंह खैहरा, राणा गुरजीत सिंह और डॉ. धर्मवीर गांधी को सह–अध्यक्ष (को–चेयरपर्सन) बनाया गया है।

वहीं, इलेक्शन मैनेजमेंट एंड को–ऑर्डिनेशन कमेटी में ओपी सोनी, रजिया सुल्ताना, कुलजीत सिंह नागरा, अंगद सिंह सैनी और भारत भूषण आशु को सह–अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है।

सीबीआई का बड़ा एक्शन : हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी दीपक गहलावत रिश्वतखोरी मामले में गिरफ्तार

अंबाला। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत हरियाणा कैडर के 2012 बैच के प्ै अधिकारी दीपक गहलावत को रिश्वतखोरी के एक मामले में गिरफ्तार किया है। दीपक गहलावत वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, नई दिल्ली में तैनात हैं। ब्ठप् का आरोप है कि उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर एजेंसी की जांच में आरोपियों को राहत दिलाने का भरोसा देते हुए कथित रूप से अवैध आर्थिक लाभ की मांग की। CBI की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस मामले में 8 जून 2026 को दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह और दो निजी व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया था। शुरुआती जांच और आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई अहम तथ्य सामने आए, जिनके आधार पर जांच का दायरा बढ़ाया गया। इसी क्रम में प्ै अधिकारी दीपक गहलावत की कथित भूमिका सामने आने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। CBI का दावा है कि दीपक गहलावत ने कथित तौर पर आरोपियों से अवैध धनराशि की मांग की थी। एजेंसी के अनुसार उन्होंने यह भरोसा दिलाया था कि वह अपने प्रभाव का उपयोग कर CBI द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में राहत दिलवा सकते हैं। यह पूरा मामला पुडुचेरी में नकली दवाइयों की बिक्री से जुड़े मामलों की जांच से जुड़ा हुआ बताया गया है। CBI ने बताया कि कार्रवाई के दौरान पहले गिरफ्तार किए गए आरोपियों से करीब 25 लाख रुपये की ट्रैप राशि बरामद की गई। इसके अलावा लगभग 90 लाख रुपये नकद, कई आपत्तिजनक दस्तावेज,

डिजिटल डिवाइस और हार्ड डिस्क भी जब्त की गई हैं। एजेंसी ने मामले से जुड़े विभिन्न ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाकर कई महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए हैं। गिरफ्तारी के बाद CBI अब IPS अधिकारी से कथित लेन–देन, संपर्कों और पूरे नेटवर्क के संबंध में पूछताछ कर रही है। एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस कथित भ्रष्टाचार में और कौन–कौन लोग शामिल थे तथा किन मामलों में प्रभाव का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। ब्ठप् का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और आगे भी कार्रवाई की जा सकती है। हरियाणा कैडर के एक वरिष्ठ IPS अधिकारी की ब्ठप् द्वारा गिरफ्तारी को प्रशासनिक और पुलिस महकमे के लिए बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है।

आम आदमी पार्टी व कांग्रेस ने पंजाबियों के साथ विश्वासघात किया : श्वेत मलिक

पठानकोट। पठानकोट में आज पूर्व सांसद व पूर्व पंजाब भाजपा अध्यक्ष श्वेत मलिक ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर पठानकोट भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष श्री शमशेर सिंह, पूर्व मंत्री मास्टर मोहन लाल, पूर्व डिप्टी स्पीकर श्री दिनेश सिंह बब्बू, पूर्व मेयर श्री अनिल वासुदेवा, पूर्व जिला अध्यक्ष सतीश महाजन, विनोद धीमान, गजेंद्र सिंह व राज कुमार गुप्ता उपस्थित थे। मलिक ने कहा कि किसी समय पंजाब आर्थिक रूप से देश में पहले स्थान पर होता था, लेकिन पिछले 10 वर्षों के कांग्रेस व आम आदमी पार्टी की सरकारों के कुशासन के कारण पंजाब 18वें स्थान पर पहुंच गया है। राज्य के विकास, बेरोजगारी, नशा मुक्ति और भ्रष्टाचार खत्म करने को लेकर किए गए झूठे वायदों ने पंजाबियों के भविष्य पर ग्रहण लगा दिया है। मलिक ने कहा कि पहले कांग्रेस ने भ्रष्टाचार से पंजाब को लूटा तो पंजाब वासियों ने 2022 में वोट के माध्यम से कांग्रेस के पंजे से छुटकारा पाया, पर अफसोस कि बाद में आम आदमी पार्टी के नेता व वर्तमान पंजाब के सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने झूठे वायदे कर पंजाब की जनता की रीढ़ की हड्डी पर प्रहार किया और पंजाब को बर्बादी के द्वार पर खड़ा कर दिया। मलिक ने कहा कि आजकल मुख्यमंत्री भगवंत मान की एक–एक विवादित वीडियो को लेकर राजनीतिक और धार्मिक हलकों में भारी बवाल हुआ है, जिसमें अकाल तख्त साहिब द्वारा उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और मुख्यमंत्री इस पर स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं। हाल ही में 'सिख धार्मिक भावनाओं' को लेकर राज्य सरकार द्वारा बनाए गए 'जागत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम 2026' के कुछ प्रावधानों पर अकाल तख्त साहिब द्वारा आपत्तियों के बाद टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मलिक ने याद दिलाया कि कांग्रेस व आम आदमी पार्टी ने श्री राम मंदिर अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार किया था। इसके अलावा जेएनयू में 2016 में आतंकवाद समर्थक नारे लगाने वालों के समर्थन में अरविंद केजरीवाल व राहुल गांधी पहुंच गए थे। कांग्रेस व आम आदमी पार्टी ने पाकिस्तान की धरती पर पल रहे आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाने पर भारतीय सेना से सबूत मांगे थे। श्वेत मलिक ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चुनाव जीतने के तुरंत बाद 2022 में महिलाओं को 1,000 रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया था, जो एक चुनावी झांसा निकला। अब मान सरकार बनने के 51 माह बाद भी पंजाब की 1.5 करोड़ महिलाओं को बकाया 51,000 रुपये प्रति महिला कब मिलेंगे, इसका कुछ पता नहीं है। मलिक ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में आप पार्टी व कांग्रेस की लोक विरोधी सरकारों ने कोई विकास नहीं किया। व्यापारी व उद्योगपतियों की सहायता के लिए कोई योजना नहीं बनाई, बल्कि भारी टैक्सों व रंगदारी–फिरौतियों से उनका काम करना मुश्किल कर दिया है। आप सरकार ने सस्ती बिजली का झूठा वायदा किया, जबकि बिजली की दरों में कई बार वृद्धि हो चुकी है। भगवंत मान ने जहां 24 घंटे बिजली देने के बोर्ड लगाए थे, वहां भीषण गर्मी में लग रहे पावर कटों ने शहरी जनता को परेशान कर दिया है और किसान सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। श्वेत मलिक ने कहा कि युवाओं को रोजगार, भारी संख्या में सरकारी नौकरियां और बेरोजगारी भत्ता देने के जो वादे किए गए थे, वे सब झूठे निकले। इसके कारण जहां बेरोजगारी से भारी संख्या में युवा पंजाब से विदेशों व अन्य राज्यों में जा रहे हैं, वहीं 'ब्रेन ड्रेन' राज्य का ज्वलंत मुद्दा बन गया है। मलिक ने कहा कि भगवंत मान सरकार का भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा हवा–हवाई हो गया है। कांग्रेस की तरह आप पार्टी ने भी पंजाब में भ्रष्टाचार करने का रिकॉर्ड बनाया है। राज्य पर बढ़ता कर्ज और प्रशासनिक कामकाज पर उठते सवाल प्रमुख आलोचनाओं में शामिल हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब को 4 लाख करोड़ से अधिक के कर्ज के बोझ में दबा दिया है और अब पंजाब में जब कोई बच्चा जन्म लेता है, तो उस पर सरकार द्वारा थोपा गया 1.25 लाख रुपये का कर्ज होता है। मलिक ने कहा कि घर–घर नशे और ड्रग्स ने पंजाब के भविष्य को बर्बाद कर दिया है। पंजाब सरकार जनता को गुमराह कर "एक युद्ध नशे के विरुद्ध" के केवल खोखले नारे लगा रही है, जबकि धरातल पर कुछ नहीं है। मलिक ने कहा कि आप सरकार ने कर्ज माफी व सभी फसलों पर एमएसपी देने का झूठा वायदा कर अन्नदाता किसानों का भी शोषण किया। राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है, लेकिन धान–गेहूं के फसल चक्र (क्रॉप साइकिल) के कारण राज्य का भूजल स्तर खतरनाक हद तक नीचे चला गया है। इसके अलावा, पराली जलाने (जनइइसम ठनतदपदह) की समस्या पर्यावरण और प्रदूषण का एक बड़ा कारण बनी हुई है, जिसे रोकने के लिए किसानों पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की गई। सरकार की लापरवाही के कारण 2025 में 12 जिलों में 3,75,000 एकड़ फसल और खेती की जमीन पानी में डूब गई और किसान इसकी मार झेल रहे हैं। मलिक ने कहा कि राज्य में शिक्षा, सेहत और जन सुधार योजनाओं का बुरा हाल है। केंद्र की मोदी सरकार ने जहां 7वां पे कमिशन लागू कर दिया है और 8वां पे कमिशन लागू होने जा रहा है, वहीं पंजाब की भगवंत मान सरकार 7वां पे कमिशन भी लागू नहीं कर पाई, जिससे पंजाब के सरकारी कर्मचारियों से भी वादाखिलाफी हुई है। इन मुद्दों के अलावा, राज्य में कानून–व्यवस्था बनाए रखना और अवैध खनन (प्स. समहंसदक डपदपदह) पर रोक लगाना भी सरकार के सामने निरंतर चुनौतियां बनी हुई हैं।

Printed, Published,Edited, & Owned by Prakash Kumar Dhal, Printed at Promodini Publication, Main road , Chhend colony , Rourkela-15 & Published at ECR-73, Chhend Colony, Rourkela-15, Editor : Prakash kumar Dhal, Email:kalingasamachar@gmail.com , Mob: 9439951525, Ph. 0661-2646999

ओडिशा समाचार

कलिंग समाचार | राउरकेला, सोमवार 10 अगस्त 2026 | पृष्ठ-6

जेन जी को गुमराह कर रहीं बाहरी ताकतें, सीएम मोहन माझी ने दी सतर्क रहने की सलाह

भुवनेश्वर ०९/०८ (संवाददाता): ओडिशा के मुज़्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 'जेन जी' से अपील करते हुए रविवार को कहा कि वे ''उन्हें गुमराह करने और वैश्विक मंच पर भारत को कमजोर करने का प्रयास कर रही बाहरी ताकतों'' का शिकार न बनें। माझी ने राज्य स्तरीय 'हर घर तिरंगा' अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के युवाओं को सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन युवाओं को ''बाहरी ताकतों द्वारा गुमराह'' किया जा रहा है। हालांकि, मुज़्यमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि भारत के युवा देशभक्त हैं और देश को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं।

माझी ने कहा, ''मैं 'जेन जी' का आह्वान करता हूं कि वे उन बाहरी ताकतों और अदृश्य दुश्मनो से सावधान रहें जो विदेशी धरती से काम करते हैं और सोशल मीडिया के जरिए हमारे युवाओं को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के युवाओं को सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन डिजिटल युग में युवाओं को बाहरी ताकतों द्वारा गुमराह जा रहा है।'' उन्होंने कहा, ''लेकिन ये अदृश्य ताकतें अपने लक्ष्यों में कभी सफल नहीं होंगी। मेरी सलाह है कि युवा देशभक्ति को प्राथमिकता दें। युवाओं की एक ही आवाज है—हमारा देश सुरक्षित रहेगा!'' उन्होंने दावा किया कि ''कुछ बाहरी ताकतें'' डिजिटल मीडिया अभियानों के जरिए 'जेन-जी' को गुमराह करने और भारत को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं।'जेन-जी' उस पीढ़ी को कहा जाता है जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई है। यह वह युवा वर्ग है जो तकनीक, इंटरनेट और सोशल मीडिया के साथ बड़ा हुआ है। इन्हें डिजिटल नेटिव्स भी कहा जाता है ज़्योंकि इनका जीवन स्मार्टफोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया से जुड़ा माना गया है। मुज़्यमंत्री ने कहा, ''आज के युवाओं को ऐसी ताकतों से दूर रहना चाहिए और देश की एकता के लिए काम करना चाहिए।'' माझी ने कहा कि युवा बाहरी ताकतों के मंसूबों के आगे नहीं झुकेंगे।

उन्होंने कहा, ''कोई भी बाहरी ताकत भारत के युवाओं को कमजोर नहीं कर सकती। आज की तिरंगा यात्रा का उद्देश्य एकजुट रहना और बाहरी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देना है।'' उन्होंने युवाओं को भारत का भविष्य बताते हुए कहा कि ये वर्ग देश को ''विश्वगुरु'' के रूप में विकसित करेगा। माझी ने कहा, ''मैं ओडिशा के सभी युवाओं का आह्वान करता हूं कि वे आगे आएं और विकसित भारत का निर्माण करें।'' मुज़्यमंत्री की यह टिप्पणी संबलपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद धर्मेंद्र प्रधान के उस दावे के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) प्रश्नपत्र लीक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान 'जेन-जी' को ''गुमराह'' करने की कोशिश की गई, इसी कारण उन्हें केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। प्रधान ने कहा था, ''जेन-जी हमारे बच्चे हैं। कुछ लोगों ने उन्हें गुमराह करने की कोशिश की। तब मेरा कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं था।

भारत में हर साल कम से कम दो करोड़ बच्चे पैदा होते हैं। पिछले 10 वर्षों के दौरान 20 करोड़ बच्चों का जन्म हुआ। उनकी अपनी आकांक्षाएं हैं, और वे भारत को 'विश्वगुरु' बनाएंगे।

आरएसपी में परियोजना निश्चय के अंतर्गत क्षमता एवं दक्षता विकास प्रशिक्षण आयोजित

राउरकेला ०९/०८ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) में परियोजना निश्चय के अंतर्गत संचालित क्षमता एवं दक्षता विकास पहल के तहत ज्ञानार्जन एवं विकास (एल.एंड डी.) विभाग के गोपबंधु ऑडिटोरियम में विद्युत सुरक्षा तथा सामग्री प्रबंधन विषयों पर अनिवार्य दक्षता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में संयंत्र के विभिन्न विभागों से लगभग 160 प्रतिभागियों ने शामिल थे, जिनमें अप्रेंटिस प्रशिक्षु एवं संविदा पर्यवेक्षक भी भाग लिये। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों की कार्य दक्षता में वृद्धि करना तथा कार्यस्थल पर सुरक्षा संस्कृति को और अधिक सुदृढ़ बनाना था। कार्यक्रम के समापन सत्र की अध्यक्षता महा प्रबंधक (एस.ई.डी.), श्री अबकास बेहेरा ने की। उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त ज्ञान को दैनिक कार्य व्यवहार में प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने प्रतिभागियों से लाइन ऑफ फायर से संबंधित संभावित खतरों की सक्रिय रूप से पहचान करने, उनके संभावित दुष्परिणामों को समझने तथा ऐसे जोखिमों को समाप्त करने के लिए प्रभावी निवारक एवं सुधारात्मक उपाय अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने भविष्य में आयोजित होने वाले दक्षता विकास कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रतिभागियों से अपने सुझाव एवं फीडबैक साझा करने का भी आग्रह किया। मटेरियल हैंडलिंग विषय पर सत्र का संचालन उप प्रबंधक (एच.एस.एम.-2), श्री भक्तहरि महापात्र ने किया। उन्होंने सुरक्षित सामग्री प्रबंधन की प्रक्रियाओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए विशेष रूप से लाइन ऑफ फायर से जुड़े खतरों पर चर्चा की। उन्होंने इन जोखिमों के कारणों, संभावित प्रभावों तथा उनसे बचाव के लिए अपनाए जाने वाले आवश्यक निवारक उपायों की जानकारी दी, जिससे कार्यस्थल को अधिक सुरक्षित बनाया जा सके।

विद्युत सुरक्षा विषय पर सत्र सहायक महा प्रबंधक (पी.डी.), श्री डी.जी.सेठी द्वारा लिया गया। उन्होंने प्रतिभागियों को विद्युत संबंधी जोखिमों, सुरक्षित कार्य पद्धतियों, पूर्व में हुई घटनाओं से प्राप्त सीख तथा विशेष रूप से वर्षा ऋतु के दौरान कार्य करते समय बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ प्रबंधक (एल.एंड डी.), सुश्री ज्योतिर्मयी राउतिया तथा सहायक प्रबंधक (सुरक्षा), सुश्री प्रज्ञा नाथ ने किया।

10.29 करोड़ से आकांक्षी जिला रायगड़ा में विकास की राह मजबूत करेगा एमसीएल

संबलपुर ०९/०८ (संवाददाता): महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) ने समावेशी विकास एवं ग्रामीण विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुनीगुड़ा प्रखंड में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए रायगड़ा जिला प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।एमसीएल अपने सीएसआर पहल के तहत रायगड़ा जिला प्रशासन को 10.29 करोड़ की विज़ीय सहायता प्रदान करेगा। इस राशि से मुनीगुड़ा प्रखंड के विभिन्न गाँवों में 8 ग्रामीण सड़कों का निर्माण, कुल 10.3 किलोमीटर सड़क, 24 पुलियों तथा 2,980 मीटर लंबाई की नालियों का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना आकांक्षी जिला विकास योजना का हिस्सा है तथा जिले के दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में ग्रामीण संपर्क व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से क्रियान्वित की जा रही है।

इस परियोजना से लगभग 3,000 लोगों, जिनमें मुज्य रूप से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs) के लोग शामिल हैं, को लाभ मिलेगा। दुर्गम एवं पहाड़ी क्षेत्र में सड़क संपर्क बेहतर होने से स्थानीय समुदायों की विद्यालयों, स्वास्थ्य सुविधाओं, बाजारों, आवश्यक सेवाओं तथा सरकारी सेवाओं तक पहुँच सुगम होगी। बेहतर सड़क अवसंरचना से सामाजिक-आर्थिक विकास को गति मिलने के साथ-साथ आवागमन में सुविधा होगी तथा स्थानीय समुदायों के जीवन की गुणवज़ा में सुधार आएगा। साथ ही, क्षेत्र में सुरक्षित एवं टिकाऊ बारहमासी सड़क संपर्क सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। श्री ज्योतिरमय सिन्हा, महाप्रबंधक (सीएस आर), एमसीएल तथा श्री आशुतोष कुलकर्णी, आईएएस, कलेज़्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, रायगड़ा ने 05 अगस्त 2026 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार की पहलों के माध्यम से एमसीएल ओडिशा में सतत सामुदायिक अवसंरचना के विकास तथा समावेशी विकास में निरंतर निवेश कर रहा है। यह परियोजना सार्वजनिक परिसंपज़ियों के सृजन, भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में संपर्क व्यवस्था में सुधार तथा कमजोर जनजातीय समुदायों के दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के प्रति कंपनी के निरंतर प्रयासों को दर्शाती है।

ओडिशा को दिल्ली में मिले 66,392 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, सृजित होंगी 54,135 नौकरियां

भुवनेश्वर ०९/०८ (संवाददाता): आठ अगस्त नयी दिल्ली में दो दिवसीय निवेश संपर्क कार्यक्रम के दौरान ओडिशा को 66,392 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले जिनके तहत 54,135 नौकरियां सृजित होने की संभावना है। मुज़्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि यह कार्यक्रम शनिवार को संपन्न हुआ। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, राज्य ने 64,703 करोड़ रुपये के निवेश वाले 38 समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए और 1,689 करोड़ रुपये के निवेश आशय पत्र (आईआईएफ) प्राप्त किए। यह संपर्क कार्यक्रम शुक्रवार को आयोजित सफल 'ओडिशा फूड प्रो 2026' के बाद हुआ। इसमें मुज़्यमंत्री मोहन चरण माझी की प्रमुख निवेशकों और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ आमने-सामने की बैठकें हुईं, साथ ही खास क्षेत्रों पर केंद्रित गोलमेज चर्चाएं भी आयोजित की गईं।

माझी ने नोएडा में 'हायर' फैज़्टरी की विनिर्माण इकाई का भी दौरा किया, जहां उन्होंने कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों और तकनीशियनों से बातचीत की और कंपनी की विनिर्माण प्रक्रियाओं और प्रणालियों का जायजा लिया। बयान में कहा गया है कि इस दौरे से अत्याधुनिक विनिर्माण के तौर-तरीकों को समझने और राज्य के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के संभावित अवसरों का पता लगाने का मौका मिला, खासकर इलेज़्ट्रॉनिज़्स, टिकाऊ उपभोक्ता सामान, आपूर्ति श्रृंखला और सहायक उद्योगों के क्षेत्र में। माझी ने कहा, ''ओडिशा एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बना रहा है जहां उद्योगों का विकास हो सके, नौकरियां सृजित की जा सकें और दीर्घकालिक मूल्य निर्माण किया जा सके। हमारा ध्यान केवल निवेश लाने पर ही नहीं, बल्कि रोजगार पैदा करने, स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला को मज़बूत करने और युवाओं के लिए नए मौके बनाने पर भी है। हम चाहते हैं कि निवेशक ओडिशा को विकास के लिए एक भरोसेमंद और लंबे समय के पार्टनर के तौर पर देखें।

चिटफंड घोटाले के आरोपी को तमिलनाडु से किया गिरफ्तार

भुवनेश्वर ०९/०८ (संवाददाता): ओडिशा में लंबे समय से चल रही चिटफंड घोटाले की जांच के तहत एक बड़ी सफलता में केंद्रीय अन्वेषण ज़्यूरो (सीबीआई) ने शिवकुमार गंगाधरण को गिरज़्तार किया है, जो कई वर्षों से फरार था।उसे तमिलनाडु के कूनूर से भुवनेश्वर सीबीआई कार्यालय की एक टीम ने गिरज़्तार किया। शिवकुमार गंगाधरण, राइटमैज़्स टेज़्नोट्रेड इंटरनेशनल लिमिटेड का पूर्व निदेशक था और वह 2018 से गिरज़्तारी से बचता फिर रहा था।सीबाआई अधिकारियों के अनुसार, वह बार-बार अपना ठिकाना बदलता रहा, ताकि जांच एजेंसियों को गुमराह कर सके और उसने अपनी असली पहचान छिपाने के लिए फर्जी पहचान पत्रों का इस्तेमाल किया। विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिलने के बाद, सीबीआई टीम ने तमिलनाडु में एक गुप्त ऑपरेशन शुरू किया और अंतत: उसे कूनूर में पकड़ लिया, जहां वह एक नकली नाम से रह रहा था। गंगाधरण के खिलाफ चिटफंड धोखाधड़ी का मामला 2014 से जुड़ा है, जब कई निवेशकों ने उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर आर्थिक धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज कराई थीं। आरोप है कि उसकी कंपनी ने लोगों से भारी रकम यह कहकर ली थी कि उन्हें ऊंचा मुनाफा मिलेगा।इसके बाद साल 2019 में कई बार समन जारी होने के बावजूद जब वह अदालत में पेश नहीं हुआ और उसका पता नहीं चला, तब अदालत ने उसे आधिकारिक रूप से अपराधी घोषित कर दिया था।गिरज़्तारी के बाद आरोपी को भुवनेश्वर लाया गया और विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।अधिकारियों ने बताया कि आगे की पूछताछ में घोटाले के दायरे और उन लोगों की पहचान करने की कोशिश की जाएगी, जिन्होंने उसे फरारी के दौरान सहायता दी। यह गिरज़्तारी ओडिशा में विज़ीय धोखाधड़ी और चिटफंड घोटालों के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है।एजेंसी ने यह दोहराया है कि वह सभी दोषियों को न्याय के कटघरे तक लाने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे उन्हें पकड़ने में जितना भी समय ज़्यों न लगे। सूत्रों के अनुसार, अब सीबीआई की प्राथमिकता घोटाले से निकाले गए पैसों की बरामदगी और पीड़ितों को मुआवजा दिलाने पर होगी। मामले की आगे जांच जारी है।

राउरकेला इस्पात संयंत्र दीपिका हस्त करघा के माध्यम से ओडिशा की हथकरघा विरासत को दे रहा है बढ़ावा

राउरकेला ०९/०८ (संवाददाता): जैसा कि राष्ट्र 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाता है, सेल, राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी) अपनी निरंतर सीएसआर पहल, दीपिका हस्त करघा के माध्यम से महिलाओं के लिए कौशल विकास और आजीविका के अवसर पैदा करते हुए भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को संरक्षित करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि कर रहा है। 2 अज़्टूबर, 2012 को दीपिका महिला जागृति संस्थान, सेज़्टर-2 में स्थापित, %दीपिका हस्त करघा% एक अनूठी पहल है जो परंपरा, कौशल और महिला सशक्तिकरण को एक साथ लाती है। हथकरघा बुनाई केंद्र की स्थापना आरएसपी द्वारा अपनी सीएसआर पहल के तहत की गई थी और इसका पोषण राउरकेला के एक प्रमुख सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन दीपिका महिला संघती द्वारा

किया जा रहा है। एक दशक से अधिक समय से, केंद्र युवा महिलाओं को, विशेष रूप से आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों से, हथकरघा बुनाई के पारंपरिक शिल्प को सीखने और टिकाऊ आजीविका के लिए कौशल विकसित करने का अवसर प्रदान कर रहा है। केंद्र में शामिल होने वाले कई प्रशिक्षुओं के पास सीमित शैक्षिक अवसर थे और बहुत कम या कोई पूर्व तकनीकी जोखिम नहीं था। संरचित प्रशिक्षण और व्यावहारिक अज़्यास के माध्यम से, उन्होंने धीरे-धीरे बुनाई के विभिन्न पहलुओं में विशेषज़्ता हासिल की है। प्रशिक्षण में पूरी हथकरघा प्रक्रिया शामिल है, जो धागा लपेटने और तैयार करने जैसी शुरुआती गतिविधियों से लेकर फ्रेम और पिट लूम पर बुनाई तक की प्रक्रिया शामिल है। प्रशिक्षु जटिल रूप से डिज़ाइन किए गए कपास और रेशम की साड़ियों और कपड़े सहित हथकरघा उत्पादों की एक श्रृंखला बनाना सीखते हैं, जिससे पारंपरिक शिल्प कौशल और व्यावहारिक उत्पादन कौशल दोनों प्राप्त होते हैं। वर्तमान में, केंद्र में 11 प्रशिक्षु हैं जो बुनाई की बारीकियों को सीख रहे हैं। यह पहल एक सहायक वातावरण प्रदान करके प्रशिक्षण से परे जाती है जहां महिलाएं आत्मविश्वास का निर्माण कर सकती हैं, आर्थिक स्वतंत्रता विकसित कर सकती हैं और हथकरघा क्षेत्र से जुड़े अवसरों का पता लगा सकती हैं। प्रशिक्षण अवधि के दौरान, महिलाओं को एक मासिक वज़ीफ़ा भी प्रदान किया जाता है, जिससे उन्हें अपने कौशल को विकसित करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। दीपिका हस्त करघा में बनाए गए हथकरघा उत्पादों का विपणन सेज़्टर-5 मार्केट, राउरकेला में समर्पित हाउस ऑफ़ दीपिका आउटलेट के साथ-साथ प्रदर्शनियों और अन्य प्लेटफार्मों के माध्यम से किया जाता है। यह प्रशिक्षुओं और बुनकरों को अपनी शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक अवसर प्रदान करता है और हथकरघा बुनाई की समृद्ध परंपरा को व्यापक दर्शकों तक ले जाने में मदद करता है। 2012 में अपनी स्थापना के बाद से, %दीपिका हस्त करघा% न केवल महिलाओं के सशक्तिकरण में बल्कि भारत की सदियों पुरानी हथकरघा परंपराओं के संरक्षण और प्रचार में भी योगदान दे रही हैं।